▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

अश्विन–कार्तिक 2079, अक्टूबर 2022

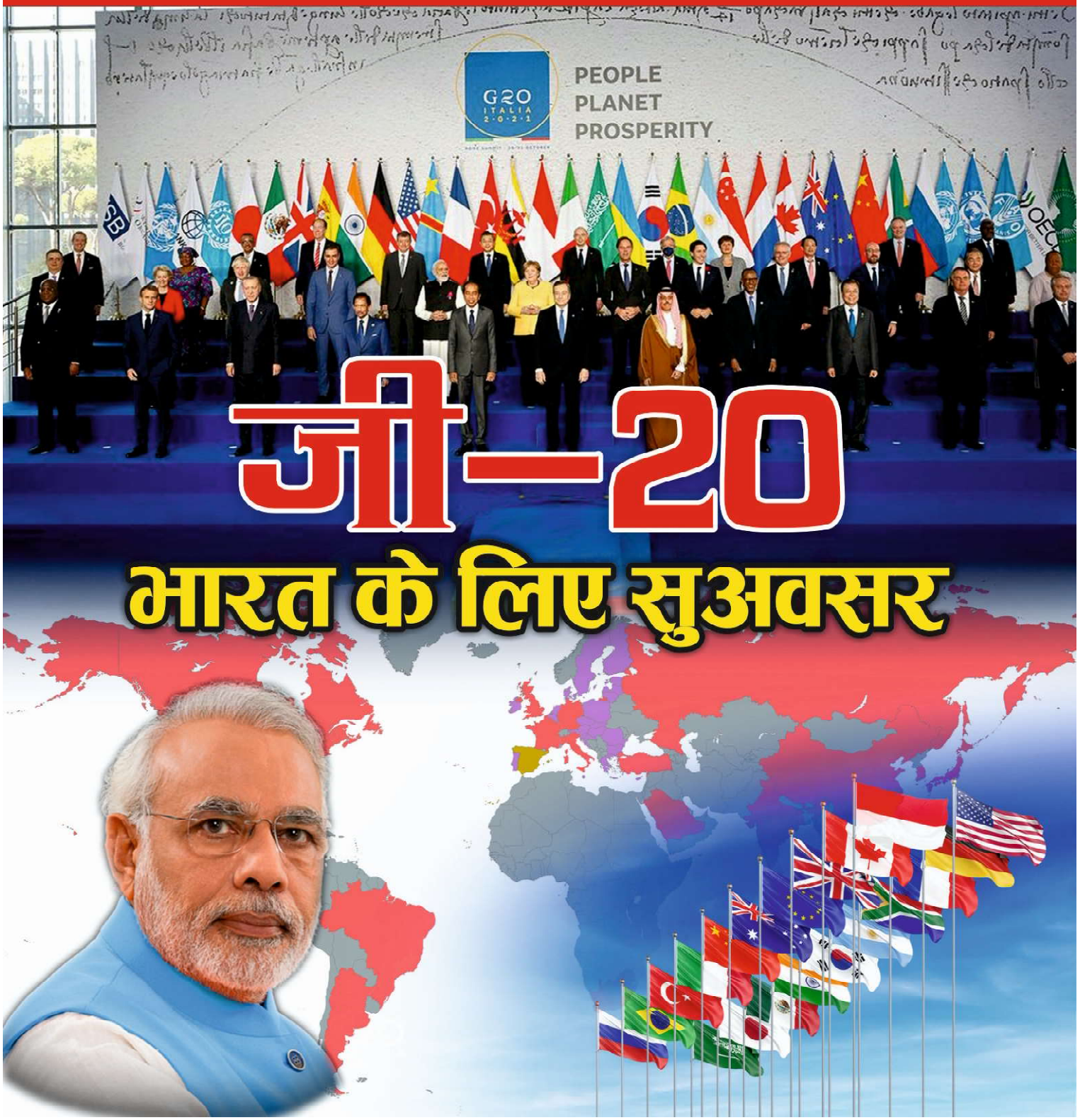

जी–20

भारत के लिए सुअवसर

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

अखिल भारतीय योजना बैठक

हरियाणा भवन, नई दिल्ली (30 सितंबर – 2 अक्टूबर 2022)

सचित्र झलक

केंद्रीय कार्यसमिति बैठक, दिल्ली

2 अक्टूबर 2022

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

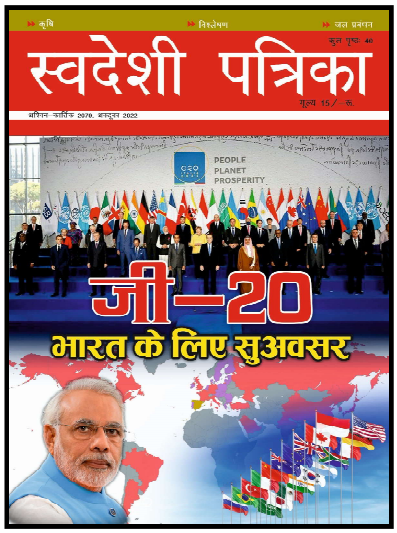

वर्ष–30, अंक–10
अश्विन–कार्तिक 2079 अक्टूबर 2022

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **35-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06
जी–20 अध्यक्षता: भारत के लिए सुअवसर
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आजकल
युद्ध रोकने की रणनीति पर सक्रिय भारत ..... अनिल तिवारी

11 आर्थिकी
भारतीय अर्थव्यवस्था: एक वास्तविक परख ..... के.के. श्रीवास्तव

13 पहल
प्राचीन ज्ञान को वैध बनाने की कवायद ..... डॉ. जया कक्कड़

15 विश्लेषण
अंतरराष्ट्रीय संगठनों की गिरती साख ..... अनिल जवलेकर

17 स्वदेशी
सर्वेभवन्तु सुखिनः यानि एकात्म मानववाद ..... स्वदेशी संवाद

19 कृषि
कॉर्पोरेट टैक्स छूट से अमीरों को ही रेवड़ियां ..... देविन्दर शर्मा

21 खेतीबारी
आखिरकार कब सुधरेंगे किसानों के दिन ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

23 योजना
आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का शहरी सूचकांक: स्वनिधि योजना ..... विकास सिन्हा

26 आर्थिकी
भारत में अधोसंरचना विकसित कर आर्थिक विकास पर जोर ..... प्रहलाद सबनानी

28 शहादत को नमन
उत्तर पूर्व भारत के गुमनाम शहीद (भाग–2) ..... विनोद जौहरी

31 पर्यटन
पर्यटन से लगेंगे रोजगार को पंख ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

32 स्वदेशी गतिविधियां
स्वावलंबन का शंखनाद – एक रपट

पाठकनामा

बेमौसम बारिश से हलकान किसान

7 अक्टूबर से हो रही लगातार वर्षा ने किसानों को फिर परेशान किया है। जहां पहले किसान वर्षा न होने के कारण सूखे से परेशान थे, अब वे बेमौसम होने वाली वर्षा से हलकान हो गये है। इस समय धान की फसल की कटाई होती है, जो बारिश के कारण रूक गई है और ध ाान की फसल बर्बाद हो रही है। देश में मंहगें डीजल, खाद, कीटनाशक खरीदकर दिन–रात एक कर किसानों ने सूखे के बावजूद अपनी फसलों को जिलाये रखा था। कहते है कि आसमान से गिरे, खजूर पर अटके वाली कहावत को चरितार्थ किया है इस बेमौसम बरसात ने।

खेती बहुतायत कुदरत के करिश्मों पर निर्भर रहती है। प्रकृति ने ऐसा नजारा प्रस्तुत किया है कि छोटे किसानों को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे हैं। तरह–तरह के सपने संजोकर खेतों में हाडतोड़ मेहनत करने वाले किसानों ने साहूकार से ले–देकर खेती को अंजाम दिया। खासकर छोटे जोत के किसान और दूसरे की जमीन किराये पर लेकर खेती करने वाले किसान मौसम की इस आंख मिचौली से हतप्रभ है।

महोदय, मैं आपकी पत्रिका के माध्यम से केंद्र तथा राज्यों की सरकारों और खेती–किसानी देखने वाले विभागों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, ताकि देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान की समय पर सुधि लिया जाए और उन्हें अचानक आ धमकी आपदा से मिल रहे आर्थिक थपेड़ों से बचाया जा सके। उपज का उचित दाम न मिलने के कारण किसान पहले से ही परेशान है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सहम–सहमकर उपलब्ध करा रही है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रय–विक्रय में गुणात्मक वृद्धि हुई है लेकिन किसानों के लिए यह दर अब भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसी ही है।

वरूण दीक्षित, गाधी, बागपत (उ.प्र.)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

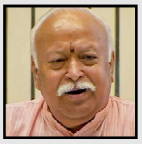

देश में एक समग्र जनसंख्या नीति बननी चाहिए और यह सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

डॉ. मोहन भागवत
सरसंघचालक, राष्ट्रीय

सरकार ने तकनीक की मदद से लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूत करने की कोशिश की है। ई–संचय, सीमा शुल्क में फेसलेस मूल्यांकन, ई–वे बिल के प्रावधान, फास्टैग के माध्यम से एक पेपरलेस एक्जिम व्यापार प्रक्रिया होनी चाहिए।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

नई शिक्षा नीति 2020, कौशल और शिक्षा को एक रूप में देखती है। हम अपने कार्यबल की सुविधा के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ कई प्रवेश और निकास ढांचे वाले डिजिटल विश्वविद्यालय के साथ आ रहे हैं।

धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री

ऑनलाईन गेम्स में टिकट के आकार को विनियमित किया जाना चाहिए। यह 50 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह एक लत है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

पुतिन को नहीं झुका पायेंगे पश्चिमी देश

फरवरी 2022 से जबसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा युक्रेन पर आक्रमण किया गया, तबसे अब तक अमरीका और उसके सहयोगी देशों सहित लगभग 50 देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाये हैं। इन आर्थिक प्रतिबंधों के अनुसार वस्तुओं की आवाजाही और वित्तीय लेनदेन समेत आर्थिक, व्यवहारों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान शामिल है। इतिहास गवाह है कि कुछ मामलों को छोड़कर पश्चिम के ये देश इन प्रतिबंधों के माध्यम से अपनी बातें शेष विश्व से मनवाने का काम करते रहे हैं। यही नहीं, कई बार प्रतिबंध लगाने की धमकी मात्र से भी अमरीका और उसके सहयोगी पश्चिम के देश विश्व में अपना दबदबा बनाते रहे हैं।

फरवरी 2022 से पूर्व भी अमरीका द्वारा रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाये जा रहे थे। लेकिन फरवरी 2022 के बाद और अधिक प्रतिबंध लगाये गये हैं। अमरीका ने अपने सहयोगी राष्ट्रों जैसे यूरोपीय संघ, इंग्लैंड, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया आदि के साथ रूस को युद्ध के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध तो लगाया ही है, साथ ही साथ रूसी बैंकों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यही नहीं रूस के सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के ऋणों को भी प्रतिबंधित किया गया है। रूस से तेल एवं गैस के आयात को भी प्रतिबंधित किया गया है। यही नहीं रूसी जहाजों के लिए भी अमरीकी बंदरगाहों में आने से रोक लगा दी गई है। यह बात समझते हुए पुतिन ने अपने हालिया बयान में कहा है कि यूरोपय देश रूस पर प्रतिबंध लगाकर अपने ही नागरिकों के जीवन स्तर की बलि तो चढ़ा ही रहे हैं, दुनिया के गरीब मुल्कों की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं।

गौरतलब है कि अमरीकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के चलते बड़ी संख्या में अमरीकी और यूरोपीय कंपनियां रूस को छोड़ रही हैं। हालांकि रूस ने तकनीकी कारणों को हवाला देते हुए जर्मनी को जाने वाली गैस पाईप लाईन 'नॉर्द स्ट्रीम' बंद कर दी है और इसके चलते यूरोपीय देश रूसी गैस और तेल पर अपनी निर्भरता घटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि तेल और आवश्यक कच्चे माल के अभाव में यूरोपीय कंपनियां ठप्प हो रही हैं और यूरोप में रोजगार प्रभावित हो रहा है। यूक्रेन विदेश मंत्री ने भी यह कहा है कि रूस, यूरोप के गृहस्थों के कुशलक्षेम को बर्बाद कर रहा है।

गौरतलब है कि 'स्विफ्ट' नाम की भुगतान प्रणाली के माध्यम से वैश्विक लेनदेन संपन्न होता रहा है। प्रतिबंधों से पूर्व 'स्विफ्ट' से अलग होकर भुगतानों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। फरवरी 2022 के बाद रूस को इस 'स्विफ्ट' प्रणाली से बेदखल कर दिया गया। अमरीका एवं उसके सहयोग राष्ट्रों को यह उम्मीद थी कि चूंकि रूस अपने निर्यातों के भुगतान को प्राप्त नहीं कर पायेगा, तो उसे उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन अमरीका और उसके सहयोगी देश अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। रूस के निर्यात घटने की बजाए पहले से भी ज्यादा बढ़ गये। ताजा जानकारी के अनुसार रूस को तेल और गैस से निर्यातों से ही इस साल 38 प्रतिशत अधिक प्राप्तियां होने वाली है।

एक ओर जहां यूरोप बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, रूस पहले से भी अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। आज अमरीका और यूरोपीय देश भयंकर मंदी के खतरे और मंहगाई से गुजर रहे हैं, और इसमें रूस एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। अमरीका में पिछली दो तिमाहियों में जीडीपी घटी है और यूरोपीय देशों की भी हालत कुछ ऐसी ही है। लेकिन कहा जा रहा है कि यूरोप में ऊर्जा संकट और धीमी ग्रोथ के कारण अब मंदी का चित्र स्पष्ट रूप से उभर रहा है। हालांकि, फिलहाल अमरीका की हालत, यूरोप जैसी नहीं है, लेकिन पिछली दो तिमाहियों में जीडीपी के संकुचन, तेजी से बढ़ रही मंहगाई (जो अगस्त 2022 में 8.3 प्रतिशत रही है) और खासतौर पर ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के चलते, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाने की नीति के चलते, अमरीका भी मंदी की चपेट में आ सकता है। समझना होगा कि यूरोप अपनी तेल की जरूरतों के लिए 25 प्रतिशत तक रूस पर निर्भर करता है। पिछले साल यूरोप के लिए 40 प्रतिशत गैस की आपूर्ति रूस से हुई थी। अब जब यूरोप और रूस के बीच तनातनी के चलते रूस से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, यूरोप भयंकर ऊर्जा संकट में जाने वाला है। यूरोपीय देशों ने अपने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को फिर से चलाने का निर्णय लिया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि पहली बार यूरोप को इन सर्दियों में ऊर्जा की कमी के चलते तापीकरण में कठिनाई हो सकती है।

हालांकि अमरीका और यूरोपीय देश ही नहीं उनके अन्य सहयोगियों को भी प्रतिबंधों और युद्ध के अन्य परिणामों से जूझना पड़ रहा है, लेकिन निकट भविष्य में यूरोप को ही इस संकट का ज्यादा असर होने वाला है। यूरोपीय देशों की मुद्राओं में भी भारी अवमूल्यन हो रहा है, वहां मंहगाई भी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्थाओं में असंतुलन भी बढ़ रहे हैं। यह पहली बार हुआ है कि अमरीकी ब्लॉक के देशों को प्रतिबंधों का इतना नुकसान हो रहा है। यूक्रेन युद्ध और उससे होने वाली समस्याओं की जड़ में यूक्रेन को 'नाटो' का सदस्य बनाना है। ऐसे में आवश्यक है कि ये देश अपने नागरिकों को आने वाली समस्याओं से बचायें। दुनिया में शांति स्थापित करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए 'नाटो' को दूसरे मुल्कों की शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रूस द्वारा यूक्रेन पर युद्ध थोपना गलत है, लेकिन 'नाटो' देशों द्वारा यूक्रेन में प्रवेश की कोशिश उसके मूल में है। यदि यूक्रेन और 'नाटो' देश अपनी हठधर्मिता छोड़ दें तो शांति भी स्थापित हो सकती है और आर्थिक संकट भी दूर हो सकते हैं।

जी-20 अध्यक्षताः भारत के लिए सुअवसर

दिसंबर 1, 2022 को भारत पर जी–20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व आ जाएगा और यह 30 नवंबर 2022 तक रहेगा। गौरतलब है कि जी–20 (यानि ग्रुप ऑफ ट्वंटी), दुनिया के बड़े विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जिसमें वर्तमान में 19 देश (अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणतंत्र, मैक्सिको, रूस, साऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमरीका) शामिल हैं। इन देशों में दुनिया की दो तिहाई जनसंख्या तो रहती ही है, दुनिया की 85 प्रतिशत जीडीपी भी इन देशों से आती है। इन देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है। दुनिया के इतने महत्पवूपर्ण देशों के समूह की अध्यक्षता के चलते लगभग 200 छोटी–बड़ी बैठकों का आयोजन भारत में होना है। कहा जा रहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

लेकिन मात्र पर्यटन ही नहीं जी–20 देशों के समूह की अध्यक्षता भारत के लिए एक सुअवसर है कि दुनिया के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में उनके समुचित समाधान प्राप्त करने हेतु प्रयास कर सके। पिछले कुछ समय से भारत ही नहीं पूरी दुनिया कुछ आर्थिक चुनौतियों से गुजर रही है। एक ओर वैश्विक मंदी, बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों की कमी से तो विश्व के कई देश जूझ ही रहे हैं, साथ ही साथ नई प्रौद्योगिकी के आगाज से जहां एक ओर हमारा जीवन सुविधापूर्ण हो रहा है, उसके कारण दुनिया भर की सरकारों के समक्ष कई चुनौतियां भी आ रही हैं। नई प्रौद्योगिकी, खासतौर पर इंटरनेट के कारण दुनिया के देशों के बीच की दूरियां अब समाप्त हो रही हैं। पुराने उद्योग–धंधे शिथिल हो रहे हैं और उनके स्थान पर नए व्यवसाय जन्म ले रहे हैं। निवेश प्राप्त करने की होड़ में प्रतिस्पर्धात्मक कराधान की ओर दुनिया बढ़ती जा रही है। यानि हर देश कारपोरेट टैक्स की दर घटाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वे निवेश के लिए सुविधाएं दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ सभी मुल्कों में कराधान भी घटता जा रहा है, जिसके कारण सरकारों के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं मिल रहा है।

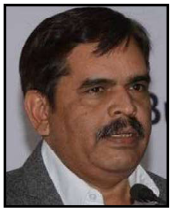

जी–20 देशों के समूह की अध्यक्षता भारत के लिए एक सुअवसर है कि दुनिया के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में उनके समुचित समाधान प्राप्त करने हेतु प्रयास कर सके।

– डॉ. अश्वनी महाजन

इसके अलावा भी दुनिया भर की सरकारें अपने मुल्कों में कर राजस्व वसूलने में तो भारी कठिनाई महसूस कर रही हैं। टेक कंपनियां ही नहीं बल्कि दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी अपने वैश्विक व्यवसाय को चलाते हुए टैक्स भुगतान से अपने को बचा रही हैं। न तो वे अपने मूल देश में कर देना चाहती हैं और न ही उन देशों में जहां वो व्यवसाय कर रही हैं।

इसके साथ ही साथ नई प्रौद्योगिकी की क्रिप्टो कैरेंसियों के चलन से टैक्स बचाते हुए और स्थापित सरकारी करेंसियों को धत्ता दिखाते हुए निजी आभासी मुद्राएं चलन में आ गई हैं। चूंकि ये मुद्राएं इंटरनेट के माध्यम से खरीदी–बेची जाती हैं, इनकी वैश्विक आवाजाही में कोई बाधा नहीं है। इन पर कर वसूलना भी एक चुनौती बनी हुई है। भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि बिना वैश्विक सहमति एवं सहकार के इन करेंसियों का नियमन संभव नहीं है।

वैश्विक न्यूनतम कर

अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने की होड़ में अधिकांश देश कारपोरेट टैक्स की दर घटाने में प्रतिस्पर्द्धा में लगे हैं। जहां आज भारत में व्यैक्तिक कर की सीमांत दर 33 प्रतिशत और कई मामलों में उससे भी अधिक है, कारपोरेट टैक्स की दर को घटाकर पहले 25 प्रतिशत और व्यवसायों के लिए मात्र 15 प्रतिशत ही कर दिया गया। उद्देश्य बताया गया कि इससे नये निवेश आकृष्ट होंगे।

कमोबेश यही हाल कई अन्य देशों का भी है। यानि कर घटाने की प्रतिस्पर्द्धा हर देश में शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कई टैक्स हैवन अलग प्रकार से करों से बचने का रास्ता देते हैं। विभिन्न देशों द्वारा दी जा रही कर रियायतों के चलते हॉट मनी और अलग–अलग देशों के अमीर लोगों का भी आकर्षण वहां होता है। भारत समेत कई देशों के अत्यधिक अमीर लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। इसके कारण निवेश तो कम आकृष्ट हो रहा है, लेकिन सरकारों का राजस्व जरूर घट रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाईडन का कहना है कि एक से अधिक देशों में काम करने वाली कंपनियों पर न्यूनतम 15 प्रतिशत कर लगाने की अनिवार्यता होनी चाहिए। इस संबंध में 136 देशों में आम सहमति भी बनी है। यदि सभी देशों में न्यूनतम कर के बारे में सहमति बनती है तो इसका लाभ सभी देशों को हो सकता है, जिससे कर राजस्व बढ़ सकता है और सरकारों के पास धनाभाव का खतरा भी टल सकता है। इस काम के लिए भारत जी–20 की अध्यक्षता के अवसर का उपयोग करते हुए इस संबंध में वैश्विक सहमति की ओर आगे बढ़ सकता है।

क्रिप्टो पर नियमन

आज कई आभासी मुद्राओं का चलन बढ़ता जा रहा है। बिटकॉन और लिथेरियम समेत कई अन्य क्रिप्टो करेंसियों (यानि आभासी मुद्राएं) चलन में हैं और कुछ सालों में उनकी कीमतें हज़ारों गुणा बढ़ चुकी हैं। स्वभाविक तौर पर उनके मूल्य में भारी उतार चढ़ाव के कारण वे लोगों (खास तौर पर युवाओं) में भारी आकर्षण का कारण बन रही हैं, क्योंकि उसमें सट्टेबाजी की संभावनाएं कही ज्यादा हैं। लोगों की गाढ़ी कमाई उसमें खप रही है।

अन्य देशों की तुलना में भारत क्रिप्टो करेंसियों के संदर्भ में अधिक प्रभावित देश है और साथ ही साथ भारत ने क्रिप्टो करेंसियों के लाभों पर कर लगाकर एक पहल भी की और क्रिप्टो करेंसियों की चुनौतियों पर समझ भी विकसित की है।

किसी एक देश की सरकार द्वारा आभासी मुद्राओं के विनियमन की संभावनाएं सीमित हैं। कई बार आतंकवादियों, नशे के व्यापारियों समेत कई प्रकार के अपराधी इन आभासी मुद्राओं में व्यवहार करते हुए सामान्य बैंकिंग चौनलों को धत्ता दिखा रहे हैं। ये आभासी मुद्राएं सभी सरकारों के लिए चिंता का सबब बन रही हैं।

हाल ही में भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसियों पर प्रभावी रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक यह मानता है कि क्रिप्टो करेंसियों के कारण देश की राजकोषीय एवं मौद्रिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इस बात से सहमति रखते हुए भी, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यह मानना है कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके जोखिमों, लाभों के आकलन के साथ–साथ साझी कराधान प्रणाली और मानक बनाए जाने की जरूरत होगी।

अन्य देशों की तुलना में भारत क्रिप्टो करेंसियों के संदर्भ में अधिक प्रभावित देश है और साथ ही साथ भारत ने क्रिप्टो करेंसियों के लाभों पर कर लगाकर एक पहल भी की और क्रिप्टो करेंसियों की चुनौतियों पर समझ भी विकसित की है।

टेक और ई–कामर्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर टैक्स

देश और अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए सरकारों को नित नये आय के स्रोत खोजने पड़ते हैं। आम तौर पर सरकारें उभरते हुए क्षेत्रों में ग्रोथ के माध्यम से कर वसूलने का काम करती हैं। लेकिन वर्तमान समय की विड़ंबना यह है कि जिन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, उन क्षेत्रों की कंपनियां अपने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस की आड़ में टैक्स देने से बच रही हैं। हालांकि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूर्व में भी यह प्रयास करती थीं। लेकिन वर्तमान टेक ई–कामर्स और सोशल मीडिया कंपनियां विभिन्न हथकंड़े अपनाकर टैक्स देने से बच रही है।

भारत में सोशल मीडिया कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (ईक्वलाईजेशन लेवी) लगाने की ओर सरकार बढ़ी है। लेकिन इस कर का आपात अत्यंत सीमित है। गूगल, फेसबुक सरीखी कंपनियां अपनी विज्ञापनों की आय पर कर देने से बच रही है और ई–कामर्स कंपनियां अपने व्यवसाय और पूंजीगत मूल्यन को बढ़ाने के लिए नकदी जलाने की रणनीति के चलते सामान्य व्यवसायिक घाटा दिखाकर टैक्स देने से बच रही है। इन कंपनियों पर अलग–ढंग से कर बसूलने की जरूरत है। खास बात यह है कि ये कंपनियां अपने मूल देशों में भी करों से बचने का प्रयास कर रही हैं। जी–20 देशों के बीच इस संबंध में चर्चा के माध्यम से दुनिया के देशों की राजकोष की समस्या के समाधान की जरूरत होगी। ❑❑

युद्ध रोकने की रणनीति पर सक्रिय भारत

अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष एक प्राकृतिक नियम है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक 'ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज' के तीसरे अध्याय में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। यह अस्तित्व का संघर्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तनों के साथ–साथ युद्ध का स्वरूप धारण कर लेता है और युद्ध हमेशा दुनिया को पीछे ले जाता रहा है। विश्व बंधुत्व और 'वसुधैवकुटुंबकम' जैसे आदर्श का हिमायती भारत अहिंसा और भाईचारा का प्रबल पक्षधर रहा है। यही कारण है कि हाल ही में हुई उज्बेकिस्तान की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संदेश दिया है कि ''आज का युग युद्ध का नहीं है। फिलवक्त के इस युद्ध के कारण दुनिया मुसीबतों में घिरती जा रही है और सबके लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं का मार्ग कठिन होता जा रहा है, यह वक्त समाधान तलाशने का है।''

पिछले लगभग 200 दिनों से चल रहे यूक्रेन–रूस युद्ध का निकष यह है कि यूक्रेन के डॉनबास इलाके में जिन खेतों में गेहूं की फसल लहराया करती थी, अब वहां गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यह क्षेत्र यूक्रेन द्वारा उत्पादित गेहूं का 8 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। सिर्फ 4 करोड़ की आबादी वाला यह देश 40 करोड़ लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। यूक्रेन द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए जिन बंदरगाहों का इस्तेमाल किया जाता है वहां सुरंग और बंकर बना दिए गए हैं। 21 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जीत के लिए 3 लाख अतिरिक्त सैनिक तैनात करने की घोषणा की। उसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ग्रुप और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साझा बयान जारी किया। यह संयुक्त बयान पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने के नतीजे से आगाह करने वाला था। रूस–यूक्रेन युद्ध से खाद्य, पोषण, ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति जिस तरह बाधित हुई है उससे दुनिया का कोई भी देश अछूता नहीं है। सिर्फ रसायनिक खाद ही की बात करें तो इसकी कीमतें साल भर में 200 गुना तक बढ़ चुकी है।

''आज का युग युद्ध का नहीं है। फिलवक्त के इस युद्ध के कारण दुनिया मुसीबतों में घिरती जा रही है और सबके लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं का मार्ग कठिन होता जा रहा है, यह वक्त समाधान तलाशने का है।''

– अनिल तिवारी

युद्ध शुरू होने के तत्काल बाद ही असर के रूप में आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि अर्थात महंगाई को बढ़ावा, भारत सहित विश्व के कई देशों में मिला है। खासकर ऊर्जा और खाद्यान्न की उपलब्धता और कीमत को लेकर कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हुई है। आपूर्ति में यह बाधा ऐसे समय में आई जब अर्थव्यवस्था में महामारी के कारण मांग पहले से ही काफी हद तक प्रभावित थी। महामारी से उत्पन्न संकट के दौर में विश्व भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय खर्चों में वृद्धि के साथ–साथ कम ब्याज दर रखने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे कि मांग में कृत्रिम वृद्धि दर्ज की जा सके। इसका भी असर कुछ हद तक महंगाई को बढ़ावा देने में रहा है। इनके कारण ईंधन और खाद्यान्न की आपूर्ति वैश्विक स्तर पर काफी प्रभावित हुई है। वस्तुओं की उपलब्धता के लिए नए समीकरण बनते रहे हैं। फलस्वरुप वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों में भी अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की जा रही है।

वर्ष 2022 के फरवरी महीने में शुरू हुए युद्ध के कारण एक तरफ रूस और यूक्रेन की ओर से गोलियां और ग्रेनेड दागे जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कारोबारी प्रतिबंधों के जरिए शह और मात का अमानवीय खेल शुरू हो गया था। युद्ध के कुछ दिनों के भीतर ही यूरोपीय कमीशन ने रूस के साथ बैंकों को सोसायटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल्स टेलीकम्युनिकेशन से अलग कर दिया। यह बैंकिंग सुविधाओं को हासिल करने वाली मैसेजिंग सर्विस है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में रूस पर प्रतिबंधों की बौछार लगा दी और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का सीधा असर उसके कारोबार पर पड़ा, क्योंकि रूस की आमदनी का 40 प्रतिशत हिस्सा निर्यात से आता है। इसलिए तेल एवं गैस की आपूर्ति सबसे पहले बाधित हुई। उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से तेल टैंकरों व जहाज को क्रेडिट गारंटी व बीमा नहीं मिल पाया, यहां तक कि जर्मनी जो गैस के लिए सबसे ज्यादा रूस पर निर्भर था, उसने यूरोप की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन आरडी स्ट्रीम टू के परिचालन पर रोक लगा दी। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सेल ने रूस के स्वामित्व वाली गैस कंपनी के साथ कारोबार बंद कर दिया। युद्ध, कारोबारी संबंधों को कैसे तहस–नहस कर देता है इसकी नुमाइश ब्रिटिश पेट्रोलियम ने युद्ध में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचकर चौकाया। कोरोना संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद की जा रही थी, वह यदि आज अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है तो उसके पीछे युद्ध जनित ऊर्जा संकट अहम है।

दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सेल ने रूस के स्वामित्व वाली गैस कंपनी के साथ कारोबार बंद कर दिया। युद्ध, कारोबारी संबंधों को कैसे तहस-नहस कर देता है इसकी नुमाइश ब्रिटिश पेट्रोलियम ने युद्ध में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचकर चौकाया।

युद्ध शुरू होने के बाद 21 देशों ने खाद्य वस्तुओं के निर्यात से जुड़े 30 प्रतिबंध लगाए। यू.एन.ओ. के मुताबिक रूस और यूक्रेन गेहूं के वैश्विक कारोबार में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं, 60 प्रतिशत सूरजमुखी के तेल और जौ के कुल निर्यात में 30 प्रतिशत हिस्सा रूस और यूक्रेन का होता है। सोमालिया जैसे कुछ देश गेहूं के लिए पूरी तरह यूक्रेन पर निर्भर है। लाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस की आक्रामकता की एक बड़ी वजह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रूस का सबसे अहम स्थान है। यह देश दुनिया को तेल, गैस एवं उर्वरकों के साथ ही कई जिंसों का निर्यात करता है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन तीनों मिलकर वैश्विक बाजारों में उर्वरक के कुल कारोबार में एक तिहाई के हिस्सेदार हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 25 फ़ीसदी यूरिया, 90 फ़ीसदी फास्फेट और 100 प्रतिशत पोटाश आयात करता है। भारत की उर्वरक जरूरतों का भी बड़ा हिस्सा इन देशों से आता है। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने जैसी आत्मनिर्भरता हासिल की है वैसे ही ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन में अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के प्रयास तेज करने होंगे। खासतौर पर फास्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों के आयात के विकल्प मजबूत करने होंगे। यदि भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मौजूद फास्फेट भंडार से उर्वरक बनाने के काम को गति देता है तो निश्चित रूप से इसके दीर्घकालिक लाभ होंगे।

हालांकि भारत ने रूस से कम दर पर तेल और गैस आयात करने की कोशिश की है। वही खाद्यान्न के निर्यात को अपनी आंतरिक जरूरतों के हिसाब से प्रबंधित करने के प्रयास भी किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक

विकास के लिए महत्वपूर्ण यह है कि ऊर्जा जरूरतों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता को सीमित किया जाए। ऐसा देश में सीमित उपलब्धता के कारण भारत की पेट्रोलियम जरूरतों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए कहा जा सकता है। किसी भी वैश्विक उथल–पुथल का असर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पर पड़ता ही है, तो एक सफल राष्ट्र के लिए ऊर्जा और ईंधन के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। देर से ही सही अब पेट्रोलियम और गैस के अतिरिक्त ऊर्जा के अन्य स्रोतों को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसे नीतिगत प्रयास सकारात्मक संकेत देते हैं। इसके लिए जरूरी तकनीक और आधारभूत संरचना बढ़ाने के प्रयासों को और अधिक गति देने की जरूरत है।

भारत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है – एक बड़ी और बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्नों की संचित उपलब्धता के लिए भारत कुछ हद तक वर्तमान में आयात और निर्यात के प्रबंधन पर भी निर्भर है। इसमें अनाज के अलावा खाद्य तेलों, दालों की मांग आपूर्ति में सामंजस्य बैठाना शामिल है। आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इसके लिए भी तकनीक के विकास

देर से ही सही अब पेट्रोलियम और गैस के अतिरिक्त ऊर्जा के अन्य स्रोतों को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसे नीतिगत प्रयास सकारात्मक संकेत देते हैं। इसके लिए जरूरी तकनीक और आधारभूत संरचना बढ़ाने के प्रयासों को और अधिक गति देने की जरूरत है।

और उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही नीतिगत प्रयास से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता दोनों के बढ़ाने की जरूरत है। अब जबकि भारत के बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं तो आने वाले दशक में आधारभूत संरचना के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी विकास पर ध्यान देने की भी जरूरत है। इससे एक सफल राष्ट्र के निर्माण को गति मिलेगी, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, ताकि उस पर वैश्विक घटनाओं का असर कम पड़े।

लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के परिणामों पर नजर टिकाए दुनिया उस पक्ष को भूल गई है, जिसमें असंख्य शरणार्थी जिंदगियों को ढ़ोते हुए इधर–उधर भटक रहे हैं। इस संवेदनशील और परा आश्रित मानव पूंजी में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके लिए युद्ध के साथ–साथ खाद्य संकट जलवायु सुरक्षा सहित बहुत से आंतरिक कारण जिम्मेदार रहे हैं। इसे लेकर यूएनएससीआर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान कर रहा है कि सभी एक साथ मिलकर मानव त्रासदी से निपटने और हिंसक टकराव को सुलझाने के स्थाई समाधान ढूंढें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में पुतिन के साथ बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि 'यह युग युद्ध का नहीं है।'

कुछ देश हालांकि शुरू में आलोचना भी कर रहे थे कि भारत खुलकर रूस की निंदा नहीं कर रहा है। बाद में उन्हें समझ में आया कि निंदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन भारत जो खुलकर रूस से बात कर सकता है, वह स्थिति भी नहीं रहेगी। आखिरकार कोई होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर उससे बात कर सके। भारत में अपनी उपयोगिता इसी रूप में दुनिया को समझायी है। भारत लगातार इन मसलों पर अन्य देशों के साथ भी बात करता रहा है और भारत की बेबाक डिप्लोमेसी का परिणाम था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत के रुख को स्वीकार किया। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

भारतीय अर्थव्यवस्थाः एक वास्तविक परख

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ चुका भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। मजबूत बुनियादी ढांचा के साथ सेवा क्षेत्र में आए उछाल के चलते उद्योग जगत ने सकारात्मक रफ्तार पकड़ी है, लेकिन इन सबके बीच ओमीक्रॉन जैसे कोरोना संक्रमण की वापसी, लगातार बढ़ती महंगाई और यूक्रेन के खींचते युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी के संकेत भी दिखने लगे हैं। नवीनतम ओईसीडी अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। लेकिन बाहरी मांग में लगातार आ रही नरमी के कारण आने वाले दिनों में यह दर 5.7 प्रतिशत हो सकती है, क्योंकि कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के केवल 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान किया गया है। दरअसल वैश्विक विकास जिस गति से धीमा हो रहा है, मुद्रास्फीति की दर लगातार बढ़ रही है। हालांकि मुद्रास्फीति की दर 2023 में 8.2 प्रतिशत से घटकर 6.6 प्रतिशत तक रह सकती है, लेकिन अनुमान तभी आगे स्थायी होंगे यदि कोरोना फिर से सिर नहीं उठाएगा, यूक्रेन युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा और ऊर्जा की कीमतें और अधिक नहीं बढ़ेगी। भारत पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। मालूम हो कि अप्रैल से जून तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जोकि बाजार और आरबीआई की अपेक्षा से कम थी। अगली कुछ तिमाहियों में भी विकास दर और धीमी रहने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण कोरोना रिकवरी के बाद निर्यात के बदले पैटर्न और सेवाओं के लिए मांग का ठहर जाना था। इस क्रम में आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं, दीर्घकालिक पुनर्गठन, ऊर्जा सहित कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी तथा भू राजनीतिक तनाव भी महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। इन परिस्थितियों में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। यह सोंचकर कि निजी क्षेत्र से निवेश नहीं आ रहा है, बात नहीं बनेगी। हालांकि मार्गन स्टेनली की भविष्यवाणी से कुछ सांत्वना मिलती है कि भारत 2022–23 में एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनेगा, लेकिन आंकड़ों के पीछे छुपकर चलना व्यर्थ की कवायद है।

अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों को देखते हुए हम आंकड़ों के पीछे भागने की बजाय सभी को साथ लेकर आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें अति आत्मविश्वास के खोल से बाहर निकलकर वास्तविकता से जूझना होगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना होगा।

– के.के. श्रीवास्तव

भारत, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन यह कल्पना है। तुलनात्मक दृष्टि से ब्रिटेन के औसत नागरिक को जो नागरिक सुविधाएं उपलब्ध है, भारत अब भी उस में बहुत पीछे है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 194 देशों में 144वें स्थान पर है। एशिया में ही भारत 33वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे अमीर देश भारत की तुलना में 60 गुना अधिक है। आर्थिक असमानता के संदर्भ में विश्व असमानता रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ 10 प्रतिशत भारतीयों ने कुल आय का 57 प्रतिशत अर्जित किया और 77 प्रतिशत राष्ट्रीय संपत्ति के मालिक यही लोग थे।

टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार नीचे के 50 प्रतिशत ने केवल 13 प्रतिशत आय अर्जित की। आईएमएफ का अनुमान है कि 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2200 डालर होगी लेकिन अगर हम असमानता की डिग्री ध्यान रखते हैं और प्रति व्यक्ति आय की तुलना में सिर्फ 10 प्रतिशत की आय को बाहर कर देते हैं तो वास्तव में यह 1000 डालर ही रह जाती है। पता चलता है कि कपड़ा उद्योग में यदि कोई न्यूनतम वेतन पाने वाला सीईओ का वेतन अर्जित करना चाहता है तो उसे वहां पहुंचने में 950 साल लगेंगे।

ऑक्सफैम के हालिया अनुमानों से पता चलता है कि लगभग 60 मिलियन भारतीय केवल स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी के कारण गरीबी में चले गए हैं। महामारी के कारण बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीने को मजबूर हुए हैं। भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी 180 देशों की सूची में सबसे नीचे है।

आजादी के बाद भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। इसका मकसद यह कतई नहीं है कि हम उस प्रगति को कम करके आंक रहे हैं, बल्कि यह सावधान करने की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते आर्थिक आधार पर घमंड करने की बजाय हमें अपने वास्तविक तकलीफों को दूर करने और एक मध्यम आय वाले राष्ट्र के रूप में गिने जाने के लिए अगले 25 वर्षों में न्यूनतम 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने की जरूरत है। क्रय शक्ति समानता की दृष्टि से भारत 2022 में विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 7.24 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दुनिया में तीसरे स्थान पर है यह अच्छी बात है, फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था को आगे तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए हमें खपत और निवेश दोनों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, खासकर ऐसे में जबकि वैश्विक मांग के हमारे बचाव में आने की संभावना कम है।

हमारा निर्यात पहले से ही धीमा हो चुका है और निकट भविष्य में इसके अभी कमजोर रहने की संभावना है। सरकार भी कड़े राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी कैपेक्स की आवश्यकता होती है। वित्तमंत्री इस बात से भी खफा थी कि कारपोरेट कर की कम दर और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के बावजूद निजी क्षेत्र पर्याप्त निवेश संख्या देने में विफल रहा है। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2022 में निजी निवेश वर्ष 2013 और वर्ष 2020 की तुलना में कम रहा है।

महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के चलते जो कमी आई थी उसमें अब धीरे–धीरे सुधार हो रहा है। व्यापार में गतिशीलता बढ़ी है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2000 के उच्च विकास वाले वर्षों में देखे गए निवेश स्तरों को अभी नहीं छूपाया है। जाहिर सी बात है कि जब तक निजी कंपनियां अर्थव्यवस्था में मांग को नहीं देखती तब तक वह नई रकम लगाने को इच्छुक नहीं होती हैं। देश में घरेलू मांग के मोर्चे पर अभी भी अनिश्चितता है। कुछ वैश्विक बाधाओं के कारण नए निवेश के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि अतिरिक्त बाधाएं पैदा कर रही हैं। पहले से ही संचित माल को पहले नीचे चलाने की जरूरत है। कई बड़े व्यापारिक ब्लॉक अभी भी पहले आयात के आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाए। सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, भू राजनीतिक तनाव, विकास की उम्मीदों में कटौती और कई अन्य कारक अर्थव्यवस्था की धुंधली तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। मांग कम होने के कारण नरमी की भी संभावना बनी हुई है। नरमी जारी रहेगी तो आय भी कम होगी। निजी कंपनियां निवेश के लिए उत्साह नहीं दिखाएंगी। बल्कि यूं कहें कि अर्थव्यवस्था पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इस दृष्टि से अगर हम अपने पारंपरिक उद्योगों की चुनौतियों को देखें तो तस्वीर और भी निराशाजनक हो जाती है।

ताजा पूंजीगत व्यय में उछाल आंशिक रूप से नए परिवर्तनों के उभरने पर निर्भर करता है, जिन्हें ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। पीएलआई योजना एक सकारात्मक कदम है। निजी निवेशक अभी भी ऐसी परियोजनाओं के पहले सेट पर आर.ओ.आई. का अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा पहले पूंजीगत व्यय चक्र जिंस सुपर साइकिल के दौरान बड़े दांव लगाने वाले दिग्गजों द्वारा संचालित थे लेकिन 2011 के बाद से जिंसों के पतन के कारण इन दिग्गजों की अब ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, केवल समेकन और अधिग्रहण ही इनके द्वारा किए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में व्यवधानों ने निवेश निर्णय को कठिन बना दिया है। विदेशी पूंजी की अब पारंपरिक विनिर्माण में कम दिलचस्पी है, वह दूरसंचार बीएफएसआई खुदरा प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं। हमें कैपेक्स को आमंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रतिभा में और भूमि या मशीनरी पर कम निवेश करने की आवश्यकता है। हमें अपने नीति परिवेश को तदनुसार बदलना होगा।

अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों को देखते हुए हम आंकड़ों के पीछे भागने की बजाय सभी को साथ लेकर आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें अति आत्मविश्वास के खोल से बाहर निकलकर वास्तविकता से जूझना होगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाना होगा। ❑❑

प्राचीन ज्ञान को वैध बनाने की कवायद

हमारी प्राचीन, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को वैधानिक आधार पर प्रदान करने का मामला दिलचस्प तो है ही विवादास्पद भी है। छात्रों के भीतर भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पतंजलि योगपीठ ने एक वैदिक स्कूल बोर्ड की स्थापना की है। पीठ का मानना है कि बच्चों को मूल मनुस्मृति, वेद और उपनिषद की शिक्षा देकर उन्हें पुरातन विरासत से लैस किया जाएगा। मालूम हो कि मनुस्मृति मानव मामलों में संहिताबद्ध कानूनों वाला एक प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आलोचकों का कहना है कि इससे जाति व्यवस्था और समाज में महिलाओं की हीनता को बढ़ावा मिला है। हालांकि योगपीठ का कहना है कि मनुस्मृति के मूल पाठ में इस तरह की बुराइयां नहीं थी, जिन विकृतियों की चर्चा आजकल होती है वह सातवीं शताब्दी के आसपास इसमें जोड़ी गई। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि विकृतियों से रहित 'मूल मनुस्मृति' ग्रंथ कहां है?

सरकार ने हाल ही में भारतीय शिक्षा बोर्ड सहित कई अन्य बोर्डों को सीबीएसई बोर्ड के समकक्ष मान्यता प्रदान की है। इन बोर्डों ने फैसला किया है कि वह भारतीय ज्ञान प्रणालियों से वर्तमान अवधारणाओं को एकीकृत करते हुए आधुनिक विषयों को पढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाते समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अवधारणाओं को शामिल किया जाएगा। न्यूटन के नियमों के साथ–साथ वेदों के गुरुत्वाकर्षण नियमों की अवधारणा को भी सिखाया जाएगा। इसी तरह प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान को उदारतापूर्वक विज्ञान, भौतिकी, ज्यामिति और अन्य विषयों में मिश्रित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, ज्यामिति की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है।

पीठ का मानना है कि इससे छात्रों को अपनी प्राचीन विरासत का ज्ञान होगा तथा वे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक यात्रा पर गर्व भी करेंगे। इस बात में कोई विवाद नहीं कि हमारे पास राजनीति, अर्थशास्त्र, गणित, संगीत और यहां तक कि विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में पारंपरिक ज्ञान की समृद्ध विरासत है। सच यह भी है कि समयोपरि तथ्य और दंत कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। सैकड़ों वर्षो की गुलामी ने हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा को नष्ट किया है। हमारी स्मृति और सीखने की विधा षडयंत्रपूर्वक समाप्त की गई है। अंग्रेजों के जमाने में मैकाले ने भारतीय मेधा को कुंद करने के लिए सरकारी नीतियां थोपी थी। उन सबके बीच मनुवादी व्यवस्था ने सक्रिय रूप से जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया। ऐसे में जरूरत इस

हमें पारंपरिक ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए जो कि बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन सिर्फ अटकलबाजियों के सहारे नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान की मुख्यधारा में एकीकृत होने से पहले पूरी तरह से जांच परख कर।

– डॉ. जया कक्कड़

बात की है कि मौजूद दुर्बलताओं को दूर किया जाए और तथ्यों को कल्पनाओं से अलग किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि मूल्य आधारित मानकों के साथ–साथ व्यवहारिक रूप से वैज्ञानिक वैधता के आधार को लागू किया जाए।

हाल ही में सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद को रक्तचाप, मधुमेह, उच्च लिपिड स्तर आदि को ठीक करने का दावा करने वाले उत्पादों के विज्ञापन से परहेज करने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से उन उत्पादों को जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत प्रतिबंधित है। सरकार का कहना है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन देश के ड्रग कानूनों का उल्लंघन करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी ने सरकारी आदेश का विरोध नहीं किया है, बल्कि अपने विज्ञापनों को वापस लेने का फैसला लिया है। बावजूद कंपनी लगातार दावा करती रही है कि यह उत्पाद साक्ष्य आधारित दवाओं के हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस साक्ष्य को उपयुक्त अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अपने एक शोध में यह पाया है कि मधुमेह विरोधी आयुर्वेदिक दवा बीजीआर–34 मोटापे को कम करने के साथ–साथ पुरानी बीमारी से पीड़ित रोगी के चयापचय तंत्र में सुधार करने में प्रभावी है। संयोग से यह दवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद भारत सहित दुनिया में आयुर्वेदिक दवाओं की स्वीकृति बढ़ी है। निवारक उपायों के लिए आयुर्वेद लोगों की पहली पसंद बना है। सरकार भी औषधीय पौधों से प्राप्त परीक्षित उत्पादों को प्रतिरक्षा बुस्टर के रूप में समर्थन करती है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे उत्पाद निवारक या उपचारात्मक हैं? क्योंकि यह साक्ष्य

इसमें कोई दो राय नहीं कि आयुर्वेद का सहस्त्राब्दियों से अस्तित्व में है और लाखों लोगों की सेवा करता रहा है, लेकिन केवल विश्वास के आधार पर इसका व्यापक रूप से अपनाया जाना जोखिम भरा है।

आधारित होने की बजाय विश्वास आधारित हैं। इन पर महत्वपूर्ण शोध नहीं किया गया है। ऐसे उत्पाद आधुनिक वैज्ञानिक जांच के मामलों पर 100 प्रतिशत खरे नहीं है।

इसी तरह एनडीए सरकार ने वैकल्पिक दवाओं के चिकित्सकों को सर्जरी करने और एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार के इस निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है, प्रासंगिक अधिनियमों में हाल के संशोधनों के अनुसार शल्य और शालाक्य ब्रांच के पीजी विद्वानों को स्वतंत्र रूप से सर्जरी या उसकी प्रक्रियाओं को करने के लिए अधिकृत किया है। इसमें आपत्तियां दो कारकों से उत्पन्न होती है। एक यह कि यह वैध नहीं है और दूसरी यह कि यह पूरी तरह से उचित नहीं है। वैध प्रश्न है कि क्या वैकल्पिक दवाओं के चिकित्सक उचित योग्यता या अनुभव के बिना सर्जरी सहित आधुनिक चिकित्सा उपचार की पेशकश करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य हैं। दूसरा यह कि आयुष की पारंपरिक प्रणालियों में निहित ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हुए एलोपैथी प्रणाली को मान्यता दी गई है। हालांकि एलोपैथ और आयुर्वेद का रगड़ा कोई नया रगड़ा नहीं है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने आधुनिक चिकित्सा को पारंपरिक दवाओं के साथ एकीकृत करने की बात भी कही है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रमुख मुद्दा उपयोगकर्ताओं का कल्याण है। किसी भी कीमत पर उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि आयुर्वेद का सहस्त्राब्दियों से अस्तित्व में है और लाखों लोगों की सेवा करता रहा है, लेकिन केवल विश्वास के आधार पर इसका व्यापक रूप से अपनाया जाना जोखिम भरा है। उदाहरण के लिए कई वैज्ञानिक तथ्य प्राचीन ज्ञान से मेल नहीं खाते, क्योंकि अक्सर अटकलों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रंथों में गुर्दे ने शरीर से अपशिष्ट विषाक्त पदार्थों को छानने में कोई भूमिका नहीं निभाई को लिया जा सकता है। कई एक पारंपरिक दवाएं आवश्यक शोध के अभाव में विफल हो गई, क्योंकि पारंपरिक ज्ञान के पक्षधर वैज्ञानिक संशोधन की संभावना को स्वीकार नहीं करते। लंबे समय से लंबित होने पर भी सुधार नहीं चाहते। क्योंकि उनके मुताबिक ग्रंथों की कालातीत प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। हालांकि कई एक प्रबुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने स्वीकार किया है कि इन क्लासिकस में निहित शरीर रचना विज्ञान वैज्ञानिक जांच की परीक्षा पर खरे नहीं उतर सकते हैं। हाल के दिनों में आधुनिक उपदेशक, अभ्यासी सन्यासी और यहां तक कि आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान भी वैज्ञानिक निष्कर्षों से इतर प्राचीन अवधारणाओं को वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल तथ्यों का उपहास नहीं है, बल्कि यह अशुभ रूप से खतरनाक भी है। क्योंकि इसमें गलत निदान और उल्टा उपचार होता है। हमें पारंपरिक ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए जो कि बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन सिर्फ अटकलबाजियों के सहारे नहीं बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान की मुख्यधारा में एकीकृत होने से पहले पूरी तरह से जांच परख कर। ❑❑

अंतरराष्ट्रीय संगठनों की गिरती साख

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की एक बैठक अभी हाल में समाप्त हुई। पहले यह संगठन पांच देशों का था और अब 8 देशों का है, जिसमें भारत भी शामिल हुआ है। यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन है, जो आर्थिक और सुरक्षा में सहयोग करने की बातें करता है। वैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन मानव जाति के लिए नये नहीं है। धार्मिक संगठनों से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है। दुनिया भर में अलग–अलग देशों के राजाओं के आपसी संबंध सदियों से रहे है और उनके बीच युद्ध और समझौते, दोनों ही अपना–अपना राजनीतिक हित देखकर होते रहे है। बाद में युद्ध में पीड़ित लोगों की मदद के लिए संगठन बनें। पहले महायुद्ध के बाद शांति के प्रयासों को महत्व दिया गया और इसकी शुरुआत राष्ट्रसंघ की स्थापना से हुई। बाद में दूसरे महायुद्ध के बाद इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का रूप दिया गया और यही आज का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठन कहा जा सकता है। बाद में कई संगठन बनें और देशों के आपसी व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से सहयोग बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी दुनिया में युद्ध हो रहे है और छोटे देशों का आर्थिक शोषण भी हो रहा है। कोरोना जैसी महामारी और यूक्रेन यद्ध ने फिर एक बार ऐसे संगठनों की असहायता स्पष्ट की है और यही आज चिंता का विषय है।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दौर

दुनिया भर में कई संगठन काम करते है, इसमें देशों की सरकारों के सहयोग से काम करने वाले और गैर सरकारी तरीके से काम करने वाले दोनों प्रकार के संगठन है। यूनियन ऑफ इंटरनेशनल एसोसियन्स के अनुसार दुनिया में 75 हजार से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसमें से 42 हजार ही सक्रिय है। 300 देशों में यह संगठन काम करते है और हर साल लगभग 1200 नए संगठन बनते है। निश्चित ही आरोग्य और कई सामाजिक, पर्यावरण या आर्थिक प्रश्नों को लेकर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सरहना ही करनी होगी, जो अपने सीमित संसाधन से सेवा कार्य में लगे रहते है। लेकिन सरकारों के भागीदारी में काम करने वाले राजनीतिक संगठनों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता।

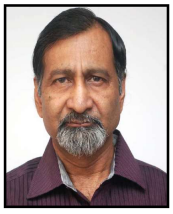

यह सच है कि बड़े संगठन जैसे की संयुक्त राष्ट्र संघ, डबल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डबल्यूएचओ वगैरे अपना काम निष्पक्षता से कर नहीं पा रहे है।
– अनिल जवलेकर

मुख्य राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय संघटन

अंतरराष्ट्रीय संगठनों की शुरुआत सही मायने में 20वीं शताब्दी में राष्ट्रसंघ की स्थापना

से हुई और वही आपसी युद्ध टालने तथा शांति के प्रयास का जरिया बना। दुनिया में स्थिरता लाने की यह एक अच्छी कोशिश थी। दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ–साथ और भी संगठन बनें। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डबल्यूटीओ, डबल्यूएचओ, यूनिसेफ़, आईएलओ, एफ़एओ, जैसे नाम सभी को परिचित है। इन कोशिशों के बावजूद क्षेत्रीय संगठन भी बनें। जैसे, यूरोपीयन यूनियन, अरब लीग, ब्रीक्स, संघाई सहयोग संगठन, कॉमन वेल्थ देशों का संगठन, सार्क संगठन, अफ्रीकी संगठन, जिसमें देश अपने क्षेत्रीय हित और क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा की बात करते दिखते है। इसी तरह कुछ ताकतवर या विकसित देशों के भी संगठन बनें। जैसे, जी–7। नाटो जैसे संगठन भी बनें, जो एक दूसरे की सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं। कुल मिलाकर, यह सारे संगठन बातें तो शांति और सहकार की करते है लेकिन इनके सदस्य देश अपनी–अपनी ताकत और वर्चस्व बनाने या बढ़ाने में लगे रहते है।

बड़े संगठनों की गिरती साख

यह सच है कि बड़े संगठन जैसे की संयुक्त राष्ट्र संघ, डबल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ़, डबल्यूएचओ वगैरे अपना काम निष्पक्षता से कर नहीं पा रहे है। संयुक्त राष्ट्रसंघ यूक्रेन–रूस युद्ध रोक नहीं पाया या शस्त्र स्पर्धा में भी कमी नहीं ला सका। बड़े देश आतंकवाद के संदर्भ में स्वार्थी भूमिका लेते दिखाई देते है। चीन का पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में रुख इसका उदाहरण है। डबल्यूटीओ की बात अब कोई सुन नहीं रहा है। सभी देश अपने–अपने हित को ध्यान में रखकर आपसी व्यापार बढ़ाने में लगे हुए है और आपसी व्यापार समझौते में ज्यादा विश्वास कर रहे है। आईएमएफ़ और वर्ल्ड बैंक लंका की स्थिति संभालने में

पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीति में बदलाव आया है और भारत समर्थ बनने का प्रयास कर रहा है और शायद इसलिए नीति और भूमिका में स्पष्टता आ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हर शांति प्रयासों में सहयोगी होने के बावजूद भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, यह सराहनीय है।

सहायक साबित नहीं हुए। डबल्यूएचओ का कोरोना संकट में जो रुख था, इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सभी देशों के सहयोग से बने अंतरराष्ट्रीय संगठनों की गिरती साख का मुख्य कारण यही है कि यह संगठन बड़े देशों के दबाव में काम करते है। दूसरे महायुद्ध के बाद बहुत सारे देश स्वतंत्र जरूर हुए लेकिन किसी न किसी गुट के हिस्सा रहे और यह बात अंतरराष्ट्रीय संगठनों के व्यवहार में साफ दिखाई देती है। आज भी रूस–चीन दुनिया के देशों को एक तरफ खिचते है तो अमरीका और यूरोप के ताकतवर देश दूसरी ओर। आर्थिक सहायता के लिए भी यह संगठन उन्हीं बड़े देशों पर निर्भर है जो छोटे देशों को हथियार पूर्ति करते है। जिन देशों का नाम ऐसे हथियार बेचकर शांति के प्रयास के लिए धन देने में आगे है उसमें अमरीका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मन, इटली, ब्रिटन आदि शामिल है।

अमरीका का दुनिया की हथियार पूर्ति में 40 प्रतिशत और रूस का 19 प्रतिशत हिस्सा है। अमरीका अकेले ही शांति मिशन की संस्थाओं को 27 प्रतिशत मदद करता है। और यही इन संगठनों की असफलता का राज है। संयुक्त राष्ट्रसंघ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ़, वर्ल्ड हैल्थ संगठन और डबल्यूटीओ जैसे संगठन कमजोर होने और छोटे तथा गरीब एवं मध्यम आय वाले देशों की सहायता न कर पाने से ही देश क्षेत्रीय संगठनों का सहारा ले रहे है तथा सामूहिक प्रयत्न की जगह एक दूसरे से सीधे संबंध बनाने के प्रयास कर रहे है।

भारत जैसे देशों को समर्थ और आत्मनिर्भर बनना होगा

भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है। यहाँ की संस्कृति सर्वसमावेशक रही है इसलिए भारत का आक्रमण और औपनिवेशी दृष्टिकोण कभी नहीं रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने अपनी शांति की भाषा कायम रखी है और वैसा ही व्यवहार किया है। लेकिन भारत की गुट निरपेक्षता की बात दुनिया के ताकतवर देशों ने नहीं मानी और भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर किसी एक गुट में शामिल होने के लिए वे कोशिश करते रहे। भारत भी हथियार के लिए बड़े देशों पर निर्भर है।

हाँ यह जरूर है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की नीति में बदलाव आया है और भारत समर्थ बनने का प्रयास कर रहा है और शायद इसलिए नीति और भूमिका में स्पष्टता आ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हर शांति प्रयासों में सहयोगी होने के बावजूद भारत आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, यह सराहनीय है। अन्य गरीब और छोटे देशों को भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के भरोसे न रहकर आत्मनिर्भरता से समर्थता की ओर बढ़ना चाहिए। आपसी सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से की हुई शांति की पहल ही युद्ध से मुक्ति दिलाने और दुनिया को खुशहाल बनाने में कारगर साबित होगी। ❑❑

पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जन्मदिन पर विशेष लेख

सर्वेभवन्तु सुखिनः यानि एकात्म मानववाद

पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्म दिनांक 25 सितंबर 1916 को जनपद मथुरा (उ.प्र.) के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भगवतीप्रसाद जी उपाध्याय एवं माता का नाम श्रीमती रामप्यारी उपाध्याय था। बचपन के साथ–साथ आपका पूर्ण जीवन ही बहुत संघर्षमय रहा था। आपकी आयु जब मात्र दो वर्ष की थी, तब वर्ष 2018 में, आपके पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इन परिस्थितियों के बीच आपका पालन पोषण आपके नानाजी के घर पर हुआ। परंतु, कुछ समय पश्चात ही आपकी माताजी का भी देहांत हो गया और जब आपकी आयु मात्र 10 वर्ष की थी तब आपके नानाजी भी चल बसे। इस प्रकार आपने बहुत छोटी सी आयु में ही अपने पूरे परिवार को खो दिया था। अब आपको अपने भाई श्री शिवदयाल जी का ही एक मात्र सहारा था। दोनों भाई अपने मामाजी के साथ रहने लगे। श्री दीनदयालजी जी अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और आपने अपने भाई को सदैव एक अभिभावक के रूप में देखा। परंतु, नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, तथा वर्ष 1934 में आपके भाई की भी मृत्यु हो गई। अब आपके साथ अपने परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा था। फिर भी आपने अपने जीवन में कभी भी अपनी जिन्दगी से हार नहीं मानी और जैसे इस पूरे देश को ही आपने अपना परिवार मान लिया था। इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आपने अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दी एवं आपने वर्ष 1936 में बीए स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। बाद में, आपने एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। शिक्षा पूर्ण करने के तुरंत बाद ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। आप आजीवन संघ के प्रचारक रहे। आप मात्र 51 वर्ष की अल्पायु में दिनांक 11 फरवरी 1968 को इस दुनिया को छोड़कर चले गये। आपने अपने जीवनकाल में कई कृतियों की रचना की थी, जिनमें शामिल हैं – एकात्म मानववाद, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, जगद्गुरु शंकराचार्य, सम्राट चन्द्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दिशा, दो योजनाएं, राजनीतिक डायरी, आदि।

चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, देश हो या विश्व हो, किसी के भी विषय में चिंतन का आधार एकांगी न होकर एकात्म होना चाहिए। इस प्रक्रिया में देश या राष्ट्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है। अतः आज की परिस्थितियों में भारत को एवं भारत की चित्ति को समग्रता से समझना जरूरी है।

– स्वदेशी संवाद

आपके बाल जीवन के कुछ प्रसंग सुनकर आपकी संवेदनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। एक बार आप आगरा में अपने नाना जी के साथ सब्जी खरीदने हेतु मंडी में गए एवं गलती से एक खोटा सिक्का सब्जी वाली माताजी को दे दिया। घर आकर जब उन्हें यह बात ध्यान में आई तो वे तुरंत उस सब्जी वाली माताजी के पास गए एवं उस माताजी के मना करने के बावजूद आपने उसकी रेजगारी में से खोटा सिक्का ढूंढकर उनको अच्छा सिक्का देकर घर वापिस आए और तब जाकर आपको संतोष हुआ। इसी प्रकार, एक बार आप पूजनीय श्री गुरु गोलवलकर जी के साथ यात्रा कर रहे थे। श्री गुरुजी दूसरी श्रेणी के डिब्बे में थे और श्री उपाध्याय जी तृतीय श्रेणी के डिब्बे में थे। श्री गुरु जी ने किसी कार्य के लिए आपको अपने दूसरी श्रेणी के डिब्बे में बुलाया और आपने श्री गुरुजी के साथ दूसरी श्रेणी के डिब्बे में कुछ समय तक यात्रा की। कार्य समाप्त होने के बाद आप वापिस तृतीय श्रेणी के डिब्बे में आ गए और आपने टीसी से सम्पर्क कर उन्हें दो स्टेशनों के बीच की दूरी का दूसरी श्रेणी का किराया अदा किया क्योंकि आपने इन दोनों स्टेशन के बीच द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर ली थी।

कालांतर में दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के आर्थिक चिंतन को एक नयी दिशा देने

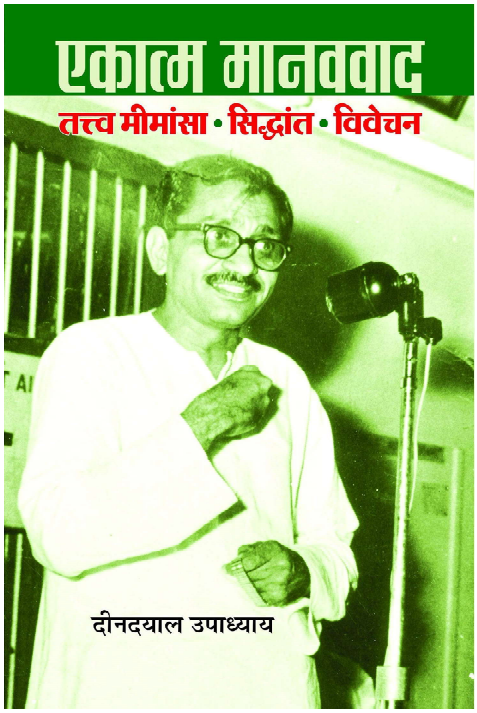

का प्रयास किया था। आपने अपने आर्थिक चिंतन को "एकात्म मानव दर्शन" के नाम से देश के सामने रखा था। यह एक समग्र दर्शन है, जिसमें आधुनिक सभ्यता की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय विचारधारा के मूल तत्वों का समावेश किया गया है। आपका मानना था कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे एक सामान्य व्यक्ति को ऊपर उठाने की सीढ़ी है, राजनीति। अपनी इस सोच को उन्होंने साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद या साम्राज्यवाद आदि से हटाकर राष्ट्रवाद का धरातल दिया। भारत का राष्ट्रवाद विश्व कल्याणकारी है क्योंकि उसने "वसुधैव कुटुम्बकम" की संकल्पना के आधार पर "सर्वे भवन्तु सुखिनः" को ही अपना अंतिम लक्ष्य माना है। यही कारण था कि अपनी राष्ट्रवादी सोच को उन्होंने "एकात्म मानववाद" के नाम से रखा। इस सोच के क्रियान्वयन से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास होगा। उसका सर्वांगीण उदय होगा। यही हम सभी भारतीयों का लक्ष्य बने और इस लक्ष्य का विस्मरण न हो, यही सोचकर इसे "अन्त्योदय योजना" का नाम दिया गया। अंतिम व्यक्ति के उदय की चिंता ही अन्त्योदय की मूल प्रेरणा है।

दरअसल प्राचीन काल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टि से भारत का दबदबा इसलिए भी था क्योंकि उस समय पर भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए ही आर्थिक गतिविधियां चलाई जाती थीं। परंतु, जब से भारतीय संस्कृति के पालन में कुछ भटकाव आया, तब से ही भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर से वर्चस्व कम होता चला गया। दूसरे, आक्रांताओं ने भी भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, को बहुत ही दरिंदगी से लूटा था। इस सबका असर यह हुआ कि ब्रिटिश राज के बाद तो कृषि उत्पादन में भी भारत अपनी आत्मनिर्भरता खो बैठा था।

इसी वजह से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ आर्थिक चिंतकों द्वारा भारत को पुनः अपनी संस्कृति अपनाते हुए आगे बढ़ने की पैरवी की गई थी। परंतु, उस समय के शासकों ने समाजवाद का चोला ओढ़ना ज़्यादा उचित समझा। जिसके चलते आर्थिक क्षेत्र में भी कोई बहुत अधिक प्रगति नहीं की जा सकी। यदि देश में उसी समय दीनदयाल उपाध्याय जी के "एकात्म मानव दर्शन" के सिद्धांत के आधार पर अपनी आर्थिक नीतियां बनायी गई होतीं तो आज देश के विकास की कहानी कुछ और ही होती।

भारतीय संस्कृति में एकात्म सभी जगह पर दिखाई देता है और अनेकता में एकता भी भारतीय संस्कृति का ही विचार है। परमात्मा के विराट दर्शन में कई अंश दिखाई देते हैं परंतु सभी एक दूसरे से जुड़े हुए भी दिखाई देते हैं। हम लोग अपने मंदिरों अथवा घरों में विभिन्न देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा करते हैं परंतु उन्हें एक रूप में भी देखते हैं। इस प्रकृति में भी समन्वय का भाव है। और तो और, प्रतिस्पर्धा में भी कहीं न कहीं जुड़ाव दिखाई देता है। यही एकात्म है। प्रकृति से अपने आप को जुड़ा महसूस किया इसीलिए भारत ने प्रकृति का उपयोग तो किया शोषण नहीं किया। भारत ने पर्यावरण की चिन्ता इसलिए की क्योंकि हमारा दृष्टिकोण भोगवादी नहीं है। एकात्मवादी है। हम सदैव अपने आपको प्रकृति से भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हम लोग मानते हैं कि व्यक्ति का एकांगी नहीं बल्कि सर्वांगींण विकास हो और आत्मा सुखी अनुभव करे। देश के साथ ही पूरे विश्व को भी परिपूर्ण एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर चलाना आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में भी यह प्रयास किया जाता है कि स्वयंसेवकों का मानसिक एवं शारीरिक विकास हो तथा वे अपने आप को पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। एकात्म मानववाद की विचारधारा पर आगे चलकर वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को अपने आप में विकसित कर सकें। एकात्म हमें दृष्टि देता है कि हम जीवन में उदार होते जाएं और अपना जुड़ाव वैश्विक स्तर तक ले जाएं।

चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, देश हो या विश्व हो, किसी के भी विषय में चिंतन का आधार एकांगी न होकर एकात्म होना चाहिए। इस प्रक्रिया में देश या राष्ट्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है। अतः आज की परिस्थितियों में भारत को एवं भारत की चित्ति को समग्रता से समझना जरूरी है। भारत के "स्व" को जानकर अपने आप में "स्व" को जगाकर, देश के "स्व" को गौरवान्वित कर पूरे विश्व में भारत के "स्व" को प्रतिष्ठित करें, आज के संदर्भ में यही भारतीय नागरिकों से अपेक्षा है। ❑❑

(प्रहलाद सबनानी के मेल से प्राप्त तथा स्वदेशी पत्रिका द्वारा संपादित)

कॉर्पोरेट टैक्स छूट से अमीरों को ही रेवड़ियां

आर्थिक जगत की साप्ताहिक पत्रिका के दिसंबर, 2020 के अंक में बताया गया कि किस तरह पिछले 50 सालों से अमीरों को मिलने वाली टैक्स–छूट का अपेक्षित प्रभाव समाज की निचली सतह तक नहीं पहुंच पाया। परिष्कृत सांख्यिकीय कार्यविधि का उपयोग करते हुए और 18 विकसित मुल्कों द्वारा अपनाई आर्थिक नीतियों के परिप्रेक्ष्य में, लंदन के किंग्स कॉलेज के दो अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि अधिकांश लोग जो तर्क सदा देते आए हैं, जाहिर है वह प्रयोग–सिद्ध सबूतों के बिना है।

प्रमाण अब सामने है। जहां बहुत से भारतीय अर्थशास्त्रियों द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की जरूरत को न्यायोचित ठहराने का यत्न किया जाता है वहीं उक्त अध्ययन, कुछ अन्य भी, निर्णयात्मक तौर पर दर्शाते हैं कि न तो टैक्स में छूट देने से अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई व न ही इससे और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिली। यह अगर कहीं मददगार हुए तो केवल आर्थिक असमानता का पाट और चौड़ा करने में, क्योंकि आसानी से मिला पैसा अति–धनाढ्यों ने अपनी जेब में रख लिया।

भारत में जहां इन दिनों 'रेवड़ी संस्कृति' को लेकर बहुत चर्चा चली हुई है और अधिकांश अखबारों में किसान सहित गरीब तबके को मुफ्त की सुविधाओं या वस्तुएं देने के खिलाफ लेख आ रहे हैं वहीं कॉर्पोरेट्स जगत की भारी–भरकम कर्ज माफी, जो किसी भी तरह खाए–अघाए अमीरों को मिठाई देने से कम नहीं है, पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सिवाय इक्का–दुक्का टीकाकारों द्वारा जिक्र किए जाने के। जिस तरह जिस और मात्रा में कॉर्पोरेट्स को मिलने वाली सब्सिडी, ऋण–माफी, टैक्स–हॉलीडे, प्रोत्साहन राशि, कर–छंटाई इत्यादि बांटे जा रहे हैं, उलटा इसका महिमामंडन किया जा रहा है।

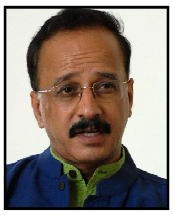

भारत में जहां इन दिनों 'रेवड़ी संस्कृति' को लेकर बहुत चर्चा चली हुई है और अधिकांश अखबारों में किसान सहित गरीब तबके को मुफ्त की सुविधाओं या वस्तुएं देने के खिलाफ लेख आ रहे हैं वहीं कॉर्पोरेट्स जगत की भारी–भरकम कर्ज माफी, जो किसी भी तरह खाए–अघाए अमीरों को मिठाई देने से कम नहीं है, पर कोई चर्चा नहीं हो रही।

– देविन्दर शर्मा

हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 'गैर–जरूरी मुफ्त की चीजों–सेवाओं' को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया है, लेकिन वैश्विक अध्ययन पक्के तौर पर स्थापित करता है कि भारत में भी कॉर्पोरेट्स को दी जाने वाली कर–कटौती शायद इसी श्रेणी में आती है। एक

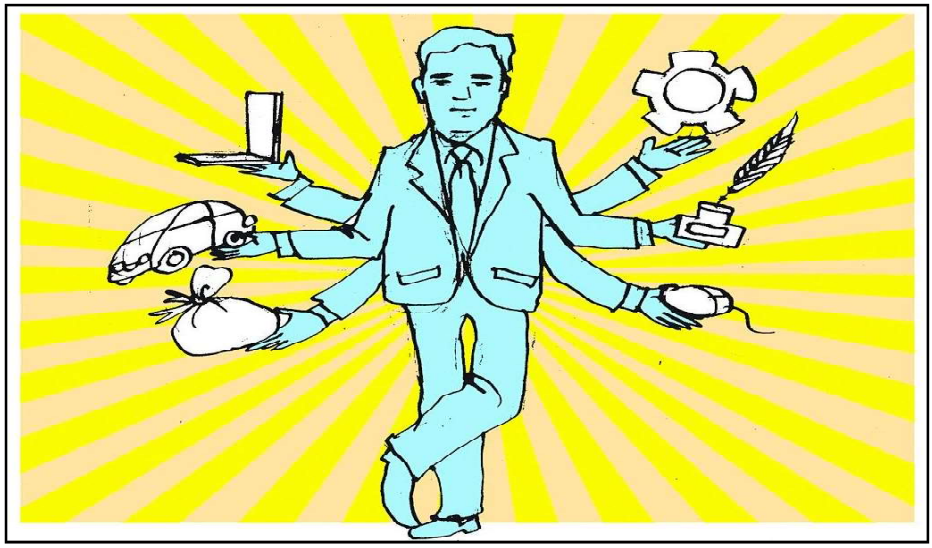

साक्षात्कार में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने–माने अर्थशास्त्री जेफरी सैच्स से एक बार पूछा गया था कि भारी–भरकम टैक्स छूटों का क्या हुआ जबकि इन्होंने न तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया और न ही अतिरिक्त रोजगार पैदा किए, इस पर उनका संक्षिप्त उत्तर था 'टैक्स रियायतों से बचा पैसा शीर्ष कंपनियों के कर्ता–धर्ताओं की जेब में जाता है'।

आईए पहले देखें कि कुछ मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों ने जो अतिरिक्त मुद्रा छापी वह किस तरह अति धनाढ्यों की जेबों में गई। 2008–09 में जब वैश्विक मंदी बनी थी, तब से लेकर यह हल, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में 'मात्रात्मक उपाय' कहा जाता है, इसके तहत अमीर मुल्कों ने 25 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की अतिरिक्त मुद्रा छापी, जिसे कम ब्याज वाले 'फेडरल बॉन्ड्स' के रूप में जारी किया गया, इनकी ब्याज दरें काफी समय तक अधिकांशतः औसत दर से 2 फीसदी कम रही और अमीरों को उपलब्ध थी। उन्होंने इस धन को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश किया और हमने देखा कि इससे उनकी शेयर मार्केट में कैसे एकदम उछाल आया। लेकिन एक तो ब्याज दरों में हालिया वृद्धि ने पहले ही उथल–पुथल मचा दी थी जिस पर संघीय नीतियों में कड़ाई होने से सूद की दरों में 4 प्रतिशत का इजाफा होने की उम्मीद है, लगता है कि अभी तक जिस तरह आजाद होकर स्टॉक मार्केट ने खेल का आनंद का लिया है, अब उस पर लगामें कसने वाली हैं और ऐसा करने की बहुत जरूरत भी है।

एक लेख में स्टेनले मार्गन के रूचिर शर्मा ने विस्तार से समझाया है कि किस तरह कोरोना महामारी के दौरान छापी गई 9 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की अतिरिक्त मुद्रा, जिसका उद्देश्य लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को संभालना था, यह करने की बजाय स्टॉक मार्केट के रास्ते अति–अमीरों की जेबों में चली गई। यह भारी–भरकम पैसा ही असल में 'रेवड़ी' है।

ऐसे लगभग 10000 से ज्यादा लोगों की सूची है जो कर्ज चुकाने की हैसियत रखने के बावजूद जान–बूझकर नहीं चुका रहे। कुछ महीने पहले, पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने वाले लगभग 2000 किसानों के खिलाफ जारी हुए वारंट रद्द किए हैं, हैरानी है कि फिर स्वैच्छिक कर्ज–खोर कैसे बख्शे जा रहे हैं।

भारत में, 2008–09 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान, तीन चरणों में 1.8 लाख करोड़ की अतिरिक्त मुद्रा छापी गई थी। सामान्य रूप में यह राहत उपाय एक साल या उसके आसपास वक्त तक खत्म कर दिया जाना चाहिए था। किंतु एक खबर के मुताबिक 'कोई नल बंद करना भूल गया', परिणामस्वरूप 'राहत' जारी रही। दूसरे शब्दों में, उद्योगों को 10 साल की अवधि में लगभग 18 लाख करोड़ की आर्थिक खैरात मिली। इसकी बजाय अगर यही धन कृषि में लगाया जाता तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाले 18 हजार रुपये वार्षिक सीधी आर्थिक सहायता के अलावा मदद मिल जाती।

इतना ही नहीं, पिछले समय के बजट दस्तावेजों में 'राजस्व माफी' नामक एक अन्य श्रेणी भी थी। प्रसन्ना मोहंती अपनी किताब 'एक बिसरा वादाः भारतीय अर्थव्यवस्था को किसने पटरी से उतारा', इसमें स्पष्ट समझाते हैं कि कैसे अपरोक्ष कराधान को 'सशर्त' और 'बिना शर्त' श्रेणियों में बांटकर सकारात्मक रूप दिया गया। फलस्वरूप 2014–15 में कॉर्पोरेट्स को ऋण माफी के जरिए मिला 5 लाख करोड़ से ज्यादा किताबों में दिखा, लेकिन बाद में इसे उपरोक्त वर्णित आंकड़ेबाजी से सिकोड़कर 1 लाख करोड़ दर्शा दिया गया। इस विशालकाय कर–माफी और छूट को छिपाने के लिए नया मासूम–सा तकनीकी नाम दियाः 'कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव'।

सितंबर 2019 में एक अन्य टैक्स माफी के रूप में 1.45 लाख करोड़ रुपये उद्योगों को दिए गए। यह वह समय था जब ज्यादातर अर्थशास्त्री सरकार को ग्रामीण बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए आर्थिक राहत देने की सलाह दे रहे थे। एक ओर कर्ज–संस्कृति को बिगाड़ने का दोष किसानों के माफ किए गए 2.53 लाख करोड़ पर मढ़ा जाता है तो वहीं यह वितंडा फैलाया जाता है कि कॉर्पोरेट जगत की कर्ज माफी से अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। हाल ही में संसद को सूचित किया गया है कि पिछले 5 सालों में कॉर्पोरेट जगत का 10 लाख करोड़ बकाया ऋण माफ किया गया है। किसानों की कर्ज माफी की बनिस्बत, जिसमें बैंकों का बकाया राज्य सरकारें भरती हैं, कॉर्पोरेट्स का सारा ऋण सिरे से छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं ऐसे लगभग 10000 से ज्यादा लोगों की सूची है जो कर्ज चुकाने की हैसियत रखने के बावजूद जान–बूझकर नहीं चुका रहे। कुछ महीने पहले, पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने वाले लगभग 2000 किसानों के खिलाफ जारी हुए वारंट रद्द किए हैं, हैरानी है कि फिर स्वैच्छिक कर्ज–खोर कैसे बख्शे जा रहे हैं। ❑❑

लेखक खाद्य एवं कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/only-the-rich-get-ravadis-from-corporate-tax-exemption-116752/

आखिरकार कब सुधरेंगे किसानों के दिन

पिछले एक साल में डीजल औसतन 15 से 20 रू. लीटर महंगा हुआ, तो पेस्टिसाइड और बीज की कीमतों में 10 से 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय आय के अनुमानित आंकड़े भी बढ़ती लागत की तरफ ही इशारा करते हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों के रेट में पिछले एक साल में 10 से 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के बीच डीजल औसत 15 से 20 रू. लीटर महंगा हुआ है, जबकि एनपीए उर्वरक की 50 किलो की बोरी 265 से 275 रू. महंगी हुई है, साल 2022–23 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र 40 रू. प्रति कुंतल और पिछले साल के लिए धान की एमएसपी में मात्र 72 रू. प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि इस दौरान कीट, रोग और खरपतवारनाशक दवाओं में 10 से 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खेती की बढ़ती लागत के अलावा किसान एमएसपी के कम रेट पर बिकती फसलों से भी परेशान हैं। यूपी के चित्रकूट जिले में गेहूं में छिड़काव के लिए यूरिया लेने वाले किसानों का कहना है कि खेती में ऐसा है कि एक कुंटल धान बेचकर एक कोई उर्वरक की एक बोरी (50 किलो) भी नहीं खरीद सकते। बस किसी तरह काम चल रहा है। एमएसपी कुछ भी हो, हमने तो 1000 रू. में धान बेचा था। डीएपी की सरकारी कीमत कुछ ओर होती है, बाजार में किसी ओर दाम में मिलता है। इसलिए खेती की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फसल के दाम नहीं बढ़े हैं। महंगाई का आलम यह है कि गन्ने की फसल में खरपतवार मारने की दवा पिछले साल जो 100 रू. थी, इस साल 200 रू. की हो गई है। जबकि 5 साल में सिर्फ 25 से लेकर 35 रू. कुंटल ही बढ़ा हैं, यानी 5 रू. प्रति कुंतल। इसे खुद ही समझा जा सकता है। बांदा के किसान राममूरत बताते हैं कि खेती करना अब कहीं से भी लाभकारी नहीं है, चूंकि हमारे पूर्वज खेती से जुड़े रहे हैं इसलिए हमारा परिवार मजबूरी में ही खेती में लगा हुआ है।

एकतरफ जहां किसान खेती की लागत की महंगाई से परेशान हैं तो दूसरी ओर आंकड़े भी बता रहे कि खेती फिर घाटे का सौदा साबित हो रही है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

एकतरफ जहां किसान खेती की लागत की महंगाई से परेशान हैं तो दूसरी ओर आंकड़े भी बता रहे कि खेती फिर घाटे का सौदा साबित हो रही है। 7 जनवरी 2022 को आये राष्ट्रीय आय के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में उत्साहजनक 4 प्रतिशत की ग्रोथ हुई, लेकिन गैर कृषि क्षेत्र में औसत ग्रोथ 10 फ़ीसदी के आसपास है। पिछले साल की अपेक्षा यह बहुत अच्छी है, जिस पर सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। राष्ट्रीय आय अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022–23 में कृषि सकल मूल्य में स्थितिकारक 5.2 फीसदी बढ़ेगा, जबकि गैर कृषि (जीबीए) इसकी तुलना में लगभग दोगुनी दर से बढ़ेगा। गैर कृषि (जीबीए) में उद्योग और सेवाओं को शामिल किया जाता है। गैर कृषि क्षेत्र में उच्च मुद्रास्फीति के कारण दो वर्ष बाद किसानों के लिए इस वर्ष खेती फिर नुकसानदायक साबित होने वाली है। बढ़ती लागत ने किसान का बजट बिगाड़ दिया है। कृषि और दूसरे क्षेत्र के आंकड़ों के

अंतर का सीधा सा मतलब है कि किसान ने खेती से जितना कुछ कमाया है, उससे ज्यादा वो डीजल, पेट्रोल, खाद, उर्वरक, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवा तक में खर्च कर रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कृषि सेक्टर में 3.4 प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ नहीं है। यह ग्रोथ ठीक है, बशर्ते कि आगे भी बनी रहे। खेती की दूसरे सेक्टर से सीधा तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेती बहुत जोखिम भरा और कुदरत का धंधा है। अगर किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिले तो खेती से जुड़े लोगों का हित हो सकता है। देश के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसानों की फसल की अच्छी कीमत मिले तो उनका लाभ होगा। खेती में बढ़ती लागत और मुनाफे के मोर्चे पर किसान की आय का मतलब है कि लागत निकालकर, फसल बेचकर जो आमदनी हो। समस्या है कि लागत ज्यादा है। दूसरी तरह किसानों की लड़ाई है कि लागत बढ़ रही है और हमें जो मिल रहा है उससे किसानों का कोटा पूरा नहीं हो रहा है। जब तक खाद्य पदार्थों की कीमतें नहीं बढ़ेगी, तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? लेकिन समस्या यह है कि सरकार फूड इन्फ्लेशन की अनुमति नहीं दे रही है। कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसके समाधान के दो तरीके हैं या तो आप उसी खेती से ज्यादा उत्पादन करें, जो कि कम समय में संभव नहीं है। क्योंकि देश में उस तरह की बीज तकनीकी और एक्सटेंशन नहीं है, या तो जो पैदा हो रहा है उसकी अच्छी कीमत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं हैं। न खेत बढ़ सकते हैं, न तुरंत सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में मंडियां बहुत जरूरी है। इसलिए भी मंडियों को ठीक किया जाना प्राथमिकता में होना चाहिए। किसान ज्यादा पैदा करके अपनी कीमत निकाल ले, इसमें समस्या नहीं है। असली समस्या तब आती है, जब किसान के खेत से निकलते ही इन चीजों के दाम गिर जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं और धान पैदा होता है, जिसका औसत रेट खुले बाजार में 1000 से 1500 के बीच रहा है। व्यापारी उन्हें उचित मूल्य नहीं देते। महाराष्ट्र के कई जिलों के किसानों ने व्यापारियों को पपीता देना बंद कर दिया था, क्योंकि व्यापारी किसान के खेत में 3 रू. किलो के रेट से पपीता खरीद रहे थे, जबकि पपीता उगाने में ही किसानों की लागत 5 से 6 रू. किलो आती है।

एनएसओ की रिपोर्ट भी बताती है कि किसान की आमदनी में फसलों से आने वाली आमदनी घटी है। सरकार के कृषि और लागत मूल्य आयोग के का भी अनुमान है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। मालूम हो कि इसी आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है।

किसान के घर में होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा मजदूरी से मिलने वाली आय होती है। भारत में जहां 67 फ़ीसदी आबादी अभी गांव में रहती है, वहां की एक बड़ी आबादी रोजगार और आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। आबादी बढ़ रही है। शहरीकरण और पारिवारिक बंटवारे में जमीन और खेत बंट रहे हैं। भारत में 42.26 प्रतिशत लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जो कि पाकिस्तान चीन से भी बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 42.6 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। जबकि पाकिस्तान में आंकड़ा 36.92 और चीन में 25.2 है। वहीं कनाडा में 1.5 है, जबकि अमेरिका में महज 1 प्रतिशत लोग खेती से अपना रोजगार चलाते हैं। वहीं चीन, अमेरिका, कनाडा में सर्विस सेंटर जैसे दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा लोग शामिल है।

पिछले 15 वर्षों में लोहा, ईंट, सरिया, सीमेंट जैसे सभी सामानों की महंगाई 20 से 30 गुना बढ़ी है, जबकि किसानों की फसलों की महंगाई मात्र 5 गुना। इस लिहाज से भी किसान 15 से 20 गुना माइनस में है। कभी खेती को मान–सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्थिति यह है कि किसी किसान के बेटे की नौकरी लग रही होती है और पैसे की जरूरत हो तो वह खेत भी बेच देता है। किसान बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेचने लग गया हैं। खेती से पलायन जारी है। डीजल से लेकर सोने तक की महंगाई को गिनाते हुए किसान हमेशा परेशान है। अधिकतर किसानों का कहना है कि अगर रवैया यही रहा तो धीरे–धीरे खेती खत्म ही हो जाएगी और खाद्य सुरक्षा का पूरा मामला कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होगा। आमदनी बढ़ाने का वादा था, लेकिन यहां तो लगातार आमदनी कम हो रही है। फसलों की लागत के मुकाबले न तो एमएसपी है और न ही बाजार भाव। ऐसे में घाटा तो होना ही है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाया है। किसान सम्मान निधि के जरिये छोटी जोत के हाथ में भी पूंजी तरलता पहुंची है। सरकार को मंडियों की व्यवस्था पर जोर देना चाहिए ताकि किसान अपनी फसल बेच सके। एक स्वागतयोग्य कदम उठाते हुए सामान्तर खुली मंडियों का प्रावधान किया था, पर स्वार्थी राजनैतिक ताकतों ने दबाव बनाकर गुमराह किया। इससे छोटे किसान मझधार में ही फंसे रह गये हैं। क्योंकि बड़ी सरकारी मंडियों तक उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए वे साहूकारों के हाथों अपनी फसल बेचने को मजबूर है। ❑❑

आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का शहरी सूचकांकः प्रधानमत्रीं स्वनिधि योजना

गरीबी और रोजगार के नगण्य होते अवसर गांव तथा छोटे शहरों के लोगों को बड़े शहर सदा ही अपनी तरफ आकर्षित करते रहे है! इसके फलस्वरूप मुख्यतः कम पढ़े–लिखे और अनिपुण लोग बड़े शहरों में आते है और शोषण का शिकार हो जाते है तथा कम भत्ते में अधिक परिश्रम करने को मजबूर होते है। गावों से शहर की ओर बढ़ती यह आबादी तथा शहरों में मौजूद सीमित संसाधन सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। मौजूदा आकड़ों के अनुसार 50 करोड़ से अधिक जनसँख्या भारत के शहरों में विद्यमान है। लगभग 20 लाख नए लोग प्रतिवर्ष इस श्रेणी में और सम्मिलित हो जाते है। सीएमआईई के आंकड़ों अनुसार शहरी बेरोजगारी की दर बीते सितंबर माह में 7.7 प्रतिशत थी। सभी जरूरमंद हाथों को काम देना सरकार के लिए एक भगीरथ कार्य है।

कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसके करने वाले की सोच बड़ी या छोटी होती है। दिल्ली के प्रीतमपुरा में ठेला लगाकर अपना व्यवसाय शुरू करने वाले श्री सतिराम यादव को आज बिट्टू टिक्की वाला के मालिक के रूप में कौन नहीं जानता है। अपनी एमबीए की पढाई बीच में ही छोड़कर एमबीए चायवाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ला बिल्लोरे को कौन नहीं जानता। स्ट्रीट वेंडिंग के माध्यम से इन जैसे कितने ही सफल लोगों ने न सिर्फ अपनी उद्यमिता को साबित किया, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये है। स्ट्रीट वेंडिंग सूक्ष्म उद्यमिता का वो प्रारूप है जो शहरी भारत के सामने खड़ी बेरोजगारी की चुनौती का समाधान कर सकने में सक्षम है। इसी प्रारूप को आगे बढ़ने का काम 'प्रधानमत्रीं स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना' करती है।

स्ट्रीट वेंडिंग सूक्ष्म उद्यमिता का वो प्रारूप है जो शहरी भारत के सामने खड़ी बेरोजगारी की चुनौती का समाधान कर सकने में सक्षम है। इसी प्रारूप को आगे बढ़ने का काम 'प्रधानमत्रीं स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना' करती है।

–विकास सिन्हा

क्या है यह योजना

यह योजना मुख्यतः शहरी पथ विक्रेताओं को सरकारी निकाय द्वारा लाइसेंस के द्वारा चिन्हित कर व्ययसाय करने का अवसर देती है तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा सब्सिडाइज्ड रेट पर ऋण मुहैया कराने में मदद करतीं है। कोरोना महामारी तथा लगातार बढ़ते लॉकडाउन

से जूझते शहरी पथ विक्रेताओं को वित्तीय मदद करने के लिए आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में मौजूद सभी शहरी पथ विक्रेता जो मार्च 2020 या उससे पहले से व्यवसाय कर रहे थे वो अपने व्यवसाय का लाइसेंस या सर्टिफिकेट को लेकर अपने क्षेत्रीय निकाय ऑफिस में जाकर इस योजना के भीतर अपने आपको पंजीकृत कराते है जिसके पश्चात उन्हें लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन जारी किया जाता है और अपने चुने गए बैंक या वित्तीय संसथान से प्रथम साल में दस हज़ार रूपए का ऋण कम से कम दस्तावेज में प्राप्त कर सकते है।

योजना का कार्यक्षेत्र

वर्तमान में यह योजना उन्ही राज्य तथा संघ राज्यों में उपलब्ध है जिन्होंने पथ विक्रेता (पथ विक्रेता की आजीविका और विनियमन की सुरक्षा) अधिनियम 2014 के अंतर्गत नियम और स्कीम अधिसूचित की है, वर्तमान में यह योजना राज्य तथा संघ राज्यों के कुल 125 शहरी निगम संकाय में कार्यान्वित है।

योजना का लक्ष्य

1. रोजगार संचालन एवं सृजनः यद्यपि इस योजना की शुरुआत कोरोना महामारी से पथ विक्रेताओं को वित्तीय पोषण के लिए किया गया था परन्तु योजना की सफलता ने यह साबित किया है कि यह योजना रोजगार सृजन तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगी। प्रथम वर्ष में दस हज़ार की धन राशि व्यवसाय को नियमित रूप से चलाने में मददगार साबित होती है। यह दस हज़ार रुपए बैंको के माध्यम से कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसे एक वर्ष की अवधी में 12 मासिक किस्तों में चुकाना होता है।

2. वित्तीय अनुशासनताः इस योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को साहूकारों के चंगुल से निकालकर संगठित वित्तीय क्षेत्र में पंजीकृत किया जा रहा है, जहाँ उन्हें उचित ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है और समय पर ऋण वापस करने के एवज में अगले साल बढ़ी हुई ऋण पात्रता उपलब्ध किया जाता है। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना में प्रोत्साहन के रूप 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है।

3. डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देनाः इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन करने पर प्रोत्साहन के रूप में कैशबैक का प्रावधान रखा गया है। प्रति माह प्रथम 50 लेन देन पर 50 रुपए, अगले 50 लेन देन पर 25 रुपए और इसके अगले हर 100 लेन देन पर 25 रुपए क्रमशः कैशबैक के रूप में पथ विक्रेताओं को प्रोत्शाहन के लिए दिया जाता है। डिजिटल लेन देन के द्वारा पथ विक्रेताओं अपने क्रेडिट इतिहास को बना पाएंगे और आने वाले समय में सही क्रेडिट मूल्यांकन के द्वारा ऋण प्राप्त कर पाएंगे।

योजना की उपलब्धिया

1. योजना के अंतर्गत अब तक तीन चरणों में 50 लाख पथ विक्रेताओं को पंजीकृत किया जा चूका है।
2. योजना के अंतर्गत 40 लाख विक्रेताओं को वित्तीय संस्थानों से दस हज़ार से बीस हज़ार रुपए तक का प्रत्येक ऋण स्वीकृत किया गया है।
3. 14 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अभी तक प्रथम वर्ष का ऋण वापसी भी पूरा कर दिया है।
4. इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को न केवल ऋण की सुविधा दी जा रही है बल्कि इन्हें सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकृत कर उनका लाभ दे रही है जिनमें प्रधानमंत्री जीवन बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि शामिल है।

योजना की चुनौतिया एवं समाधान

1. अतिक्रमणकारी छविः पथ विक्रेताओं को आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग पथ अतिक्रमणकारी समझते है, चाहे वो दूकान वाले व्यवसायी हो या रोड पर मोटरगाड़ी चलाने वाले। इन्हें न केवल दुकानदारों से बल्कि प्रशासन में मौजूद लोगों से भी सामंजस्य बना कर रखना होता है। सरकार तथा माननीय न्यायालय ने इसमें सकारात्मक भूमिका अदा की है। पथ विक्रेता (पथ विक्रेता की आजीविका और विनियमन की सुरक्षा) अधिनियम 2014 के अंतर्गत सरकार ने पथ विकरण व्यवसाय को कानूनी वैद्यता प्रदान की है। वहीं माननीय न्यायलय ने पथ विक्रयण को व्यवस्याय करने के मौलिक अधिकार के रूप में माना है, कुछ शर्तो के साथ। अब समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है।

2. जानकारी का अभावः यद्यपि सरकार द्वारा योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है पर इसे काफी नहीं माना जा सकता। पथ विक्रेताओं का एक बड़ा हिस्सा योजना या इसकी खूबियों से अनभिज्ञ है। योजना के महत्व को देखते हुए इसे जनमानस के बीच प्रचारित करने की जरूरत है।

3. तालमेल की कमीः कार्यान्वयन प्राधिकारियों में तालमेल की कमी देखी गयी है जिससे इसकी सफलता की गति धीरे हो सकती है, इसके लिए प्राधिकारियों की लगातार बैठके होनी आवश्यक है।

4. सीमित कार्यक्षेत्रः फिलहाल इस योजना को 125 शहरी निगम संकाय में कार्यान्वित किया गया है जोकि

नाकाफी माना जा रहा है योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार अधिक से अधिक शहरों में करना चाहिए। इस योजना के माध्यम से हम छोटे शहरों में लोगों को रोजगार देकर महानगरों में आने से रोक सकते है।

5. बैंकों द्वारा लोन की अस्वीकृतिः जानकारी तथा योजना प्रशिक्षण की कमी के कारण कई बार बैंकों द्वारा लोन अस्वीकृत कर दिए जाते है और कई बार जानकारी के अभाव में आवेदक लोन लेने बैंक शाखाओं में उपस्थित ही नहीं होते इसलिए योजना प्रके अंतर्गत विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण की जरूरत है।

6. ऋण की न्यूनतम राशिः मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत लाभार्थी को प्रथम वर्ष केवल दस हज़ार रुपए का ऋण प्राप्त होता है। आज के इस परिवेश में यह धनराशि बहुत कम लगती है, सरकार को इस राशि को बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरे देश का सन्दर्भः स्ट्रीट वेंडर्स के सन्दर्भ में चीन की उल्लेख करना जरूरी है।

कोरोना महामारी के पहले दमनकारी नीति अपनाने वाले चीन को कोविड–19 के बाद जब अचानक बढ़ती बेरोजगारी का सामना करना पड़ा तो चीन ने प्रीमियर ली केक्यांग की अगुआई में अपनी नीति उलटफेर की और स्ट्रीट वेंडर्स के प्रति सकारात्मक रूप अपनाया और उन्हें क़ानूनी मान्यताएं दी और इसका सफल प्रयोग चेंगडु प्रांत में किया, जिसके फलस्वरुप एक लाख से भी अधिक रोजगार का सृजन हुआ। यह अनुमान किया जा रहा है कि चीन इस नीति के प्रयोग से 5 करोड़ से अधिक लोगों को नए रोजगार दे पायेगा।

निष्कर्षः पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की उपयोगिता महज रोजगार सृजन ही नहीं है बल्कि इस योजना के माध्यम से सरकार पथ विक्रेताओं को स्वावलम्बी बनाना चाहती है, उनका पूर्णतावादी विकास, उनका सामाजिक उत्थान तथा उन्हें पूर्णतः संगठित क्षेत्र में लाना चाहती है ताकि उन्हें समग्र सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इस योजना की उपयोगिता और दूरदर्शिता को देखते हुए इस योजना की तारीफ़ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी की है और कई अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में इसे व्यष्टि अध्ययन के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

पथ विक्रेता मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा के नियमों का पालन करते हुए समाज के गरीब तथा सम्पन्न वर्ग की दूरियों को जोड़ने का काम करती है। लोगों को दिनचर्या में काम आने वाले चीज़ो को कम मूल्यों पर, कम दूरी पर, कम से कम समय पर उपलब्ध कराती है। हमारी सड़कों पर उतना ही हक़ इनका है जितना बाकी लोगों का। स्वावलंबी भारत अभियान में इनकी उपयोगिता पथ प्रदर्शक साबित हो सकती है। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

भारत में अधोसंरचना विकसित कर आर्थिक विकास पर जोर

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में उस देश की आधारिक संरचना के विकसित होने का बहुत प्रभाव पड़ता है। कच्चे माल एवं निर्मित वस्तुओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करने के उद्देश्य से इन्हें विनिर्माण इकाई से देश के बंदरगाह तक ले जाने हेतु आधारिक संरचना का विकसित होना बहुत जरूरी है। भारत में भी हाल ही के समय में इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में न केवल सड़क मार्ग का मजबूत तंत्र खड़ा कर लिया गया है अपितु अब देश में रेलवे एवं बंदरगाहों का भी एक तरह से कायाकल्प किया जा रहा है।

केंद्र सरकार भारत के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए माडल स्टेशन योजना, मार्डन स्टेशन योजना के साथ आदर्श स्टेशन योजना चला रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत देश के कई छोटे–बड़े स्टेशनों का उन्नतिकरण एवं आधुनिकीकरण का काम संचालित हो रहा है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विकास के लिए कुल 1,253 रेलवे स्टेशनों को चयनित किया गया है और अभी तक कुल 1,215 रेलवे स्टेशन विकसित किये जा चुके हैं। शेष बचे हुए 38 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए भी कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

एक अन्य योजना के अंतर्गत भारत में ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी 3 वर्षों में देश में 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किए जाने की योजना बनाई गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए बनाए गए आम बजट में इसके लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। 16 कोच वाली एक वंदे भारत ट्रेन पर 120 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वर्तमान में चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में 75 ट्रेनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी जो अगस्त 2023 तक समाप्त हो जाने की संभावना है। वर्ष 2019 में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में देश में 2 वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के बीच संचालित हो रही हैं जिनकी चलने की गति 160 किलोमीटर प्रति

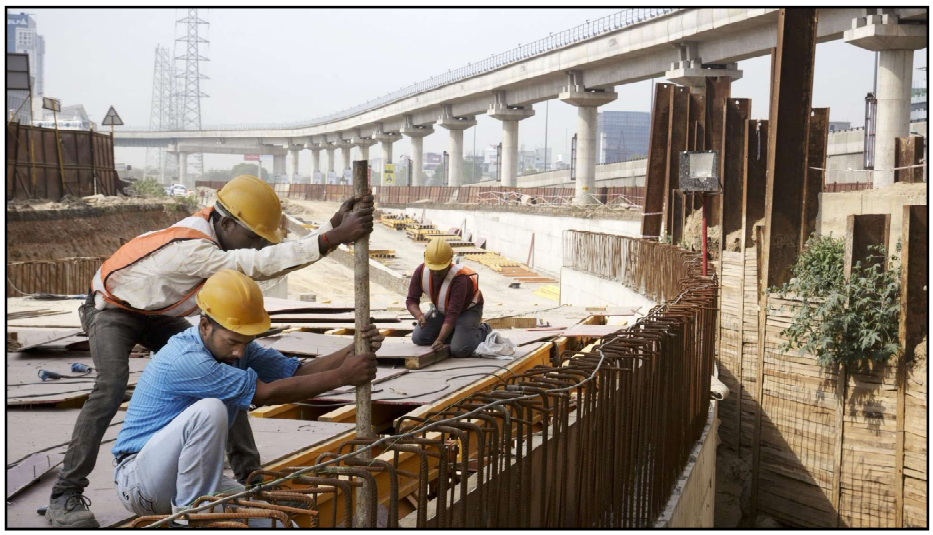

चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, देश हो या विश्व हो, किसी के भी विषय में चिंतन का आधार एकांगी न होकर एकात्म होना चाहिए। इस प्रक्रिया में देश या राष्ट्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है। अतः आज की परिस्थितियों में भारत को एवं भारत की चित्ति को समग्रता से समझना जरूरी है।

–प्रहलाद सबनानी

घंटा है, जो कि देश में अभी तक की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन की श्रेणी में शामिल है। इसी क्रम में, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक जल्दी पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे एक और योजना पर भी कार्य कर रहा है। जिसके अंतर्गत भारतीय रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उन्नतिकृत दूसरे वर्जन की 2 ट्रेनों को लाने जा रहा है। इसमें पहली ट्रेन की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि दूसरी ट्रेन की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

भारतीय रेलवे आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से भी तेजी से कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल के पहियों का भारत में ही निर्माण करने के उद्देश्य से एक विनिर्माण इकाई को भारत में लगाने के लिए एक टेंडर जारी किया है। इस विनिर्माण इकाई में प्रत्येक वर्ष कम से कम 80,000 पहियों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही रेल के पहियों का निर्यात करने की योजना भी तैयार कर ली गई है। भारतीय रेलवे ने पहली बार निजी कंपनियों को रेल पहिए के निर्माण हेतु विनिर्माण इकाई स्थापित किए जाने हेतु आमंत्रित किया है। इस 'मेक इन इंडिया' प्लांट में हाई स्पीड ट्रेनों और यात्री डिब्बों के पहियों का निर्माण किया जाएगा एवं जिसकी खरीदी रेलवे विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस प्लांट में निर्मित किए गए रेल पहियों का यूरोपीय बाजार में निर्यात भी किया जाएगा।

भारतीय रेलवे द्वारा विभिन क्षेत्रों में लगातार बढ़ाई जा रही गतिविधियों के चलते देश में रोजगार के भी लाखों अवसर निर्मित हो रहे हैं। वैसे भी देश में नागरिकों को रोजगार देने में भारतीय रेलवे का बड़ा योगदान रहा है। भारतीय रेलवे ने 8 वर्षों के दौरान लगभग 3.5 लाख नागरिकों को नौकरी प्रदान की हैं और लगभग 1.40 लाख रोजगार के अवसरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

रेलवे मार्ग के आधुनिकीकरण के साथ ही सड़क मार्ग को भी मजबूती प्रदान की जा रही है। केंद्रीय बजट में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को 1.99 लाख करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। विशेष रूप से दिल्ली–मुंबई के बीच बन रहे आठ लेन के ग्रीन एक्सप्रेस–वे के पूर्ण हो जाने के बाद कम्पनियों की लॉजिस्टिक की लागत में बहुत कमी आएगी क्योंकि पहिले दिल्ली मुंबई के बीच एक ट्रिप में जहां 54 घंटे का समय लगता था वहां अब इस नई परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत केवल 18 से 20 घंटे का समय ही लगेगा। इस प्रकार इससे न केवल परिवहन लागत में भारी कमी आएगी बल्कि CO_2 उत्सर्जन में भी बहुत बड़ी मात्रा में कमी होगी।

भारत में भारतमाला परियोजना को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले 34,800 किलोमीटर सड़क मार्ग में से अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत 6,18,686 करोड़ रुपये की लागत का 20,411 किलोमीटर लम्बे सड़क मार्ग का कार्य आबंटित किया गया है, जिसमें से अब तक 8,134 किलोमीटर सड़क के विकास का काम पूरा हो गया है। इस परियोजना के तहत गलियारों, फीडर सड़कों, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों, तटीय और बंदरगाहों से जुड़ी सड़कों, एक्सप्रेस–वे और एनएचडीपी की बकाया 10 हजार किलोमीटर की सड़कों पर भी काम शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।

इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) भी देश में 1.47 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कर रहा है। एनएचएआई 22 हरित राजमार्ग भी बना रहा है और 2024 के अंत तक भारत के सड़क ढांचे को अमेरिकी सड़कों के बराबर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। भारत में बेहतर डिजाइन और निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में 28.28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

रेलवे एवं सड़क मार्ग को विकसित किए जाने के साथ ही भारतीय बंदरगाहों का विस्तार कार्य भी तेज गति से जारी है। विशेष रूप से पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूते हुए व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को लंबी उछाल दी है एवं इस दौरान भारत के बंदरगाहों की क्षमता लगभग दुगुनी हो गई है। इस दौरान बंदरगाह क्षमता का विस्तार कर मौजूदा प्रणालियों को अधिक कुशल बनाया गया है। भारत में आज मात्रा की दृष्टि से 95 प्रतिशत व्यापार एवं मूल्य की दृष्टि से 65 प्रतिशत परिवहन समुद्र के रास्ते से हो रहा है। आज भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा पर 13 बड़े और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह कार्यरत हैं।

वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई सागरमाला परियोजना के अंतर्गत भी तेज गति से कार्य जारी है। सागरमाला परियोजना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत समुद्र और नदियों के संसाधनों का इस्तेमाल करके रोजगार के लाखों अवसर पैदा करना है एवं बंदरगाहों का विकास करना शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की 802 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा और इससे आगामी 10 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। वर्ष 2014–15 के दौरान भारतीय बंदरगाहों की स्थापित क्षमता 1531 एमटीपीए थी, जो अब 2020–21 में बढ़कर 2554.61 एमटीपीए हो गई है। ❑❑

प्रहलाद सबनानीः सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर

आजादी का अमृत काल

उत्तर पूर्व भारत के गुमनाम शहीद (भाग–2)

आजादी का अमृत काल एक पावन अवसर है, जब हम उन सभी गुमनाम स्वतन्त्रता सैनानियों को याद करें, जिन्होंने देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, औरसिक्किम जैसे राज्यों के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। स्वदेशी पत्रिका के पिछले अंक में उत्तर पूर्व के सात गुमनाम स्वातंत्र्य वीरों के विषय में संक्षिप्त परिचय दिया गया था। प्रस्तुत अंक में कुछ अन्य प्रमुख गुमनाम स्वातंत्र्य वीरों के विषय में वर्णन किया गया है।

पा तोगन संगमा

थोगन नेगमेइया संगमा का जन्म आज के पूर्व गारो पहाड़, जिला केन्द्र विलियम नगर (जिसका मूल नाम सिंगसान गिरी था) से 10 किमी दूर छिदुलिबरा ग्राम में हुआ था। 1857 के बाद अंग्रेज संपूर्ण देश पर अपना राज जमाने के लिए दमन चक्र चला रहे थे, उसी के अंतर्गत अंग्रेजों ने मेघालय और गारो पहाड़ को अपना निशाना बनाया था। अंग्रेजों ने गारो पहाड़ पर मैमेन सिंह जिले (आजकल बंगलादेश में) की ओर से आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण ग्वालापाड़ा की ओर से, और तीसरा बर्मा (म्यांमार) क्षेत्र से हुआ था। इस आक्रमण के बाद कैप्टन केरी और केप्टन विलियम ने गारो पहाड़ के तूरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और तूरा ब्रिटिश अधिकारियों का केन्द्र बन गया। थोगन नेगमेइया संगमा ने घोषणा की– "अंग्रेजों को अपने क्षेत्र पर राज नहीं करने देंगे। लोगों को उनका गुलाम नहीं बनने देंगे।" उसने क्षेत्र के युवकों की एक सेना बनायी, युवकों को प्रेरणा दी कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है तो बलिदान देना होगा। उसने गांव–गांव जाकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रचार किया और आजादी की लौ प्रज्वलित की। इधर 8 दिसम्बर, 1872 को ब्रिटिश सेना ने तूरा की ओर कूच करके अपना शिविर स्थापित कर लिया। सेना की एक टुकड़ी को ग्वालापाड़ा की ओर से तूरा भेजा गया था। थोगन नेगमेइया संगमा और उनके सहयोगियों के पास पारम्परिक ढाल, तलवार, भाला, धनुष–बाण आदि के अलावा कुछ नहीं था। थोगन और उनके सैनिक बन्दूकों से परिचित नहीं थे। अतः थोगन ने एक नया तरीका खोजा। उसने आग में एक लोहा गर्म करके लाल किया और उसको केले के तने में ढांपकर ढाल और कवच बनाए। 11 दिसम्बर, 1872 को थोगन और उनके साथियों ने अंग्रेजों के शिविर पर हमला किया और उसमें आग लगा दी। इस घटना के बाद ब्रिटिश सैनिक कुछ घबरा गए। थोगन और उनके निकट सहयोगी डालगेटसिरा के नेतृत्व में मातृभूमि की रक्षा के लिए हुए संघर्ष का सूत्रपात हो गया था। 12 दिसम्बर को फिर युद्ध शुरू हुआ तो इन लोगों की केले के तने की ढालें अंग्रेजी हथियारों के सामने टिक नहीं सकीं। ब्रिटिश अधिकारी ने षडंत्रपूर्वक थोगन को बातचीत के लिए बुलाया और गोलियों से भून डाला। थोगन शहीद हो गए। डालगेटसिरा ने स्थानीय ग्रामीणों और बच्चों के साथ युद्ध जारी रखा। लेकिन सभी अंततः शहीद हुए। अंग्रेजों ने तब संपूर्ण गारो पहाड़ पर अपना अधिकार कर लिया।

स्वदेशी पत्रिका के पिछले अंक में उत्तर पूर्व के सात गुमनाम स्वातंत्र्य वीरों के विषय में संक्षिप्त परिचय दिया गया था। प्रस्तुत अंक में कुछ अन्य प्रमुख गुमनाम स्वातंत्र्य वीरों के विषय में वर्णन किया गया है।

– विनोद जौहरी

बीर टिकेंद्रजीत सिंह

मणिपुर राज्य की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं और प्राकृतिक सौन्दर्य भारतवासियों के लिए गौरव के विषय हैं, तो उसका शौर्य, साहस एवं त्याग–बलिदान से परिपूर्ण इतिहास भारतवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। टिकेन्द्रजीत सिंह (29 दिसंबर, 1856 – 13 अगस्त, 1891) स्वतंत्र मणिपुर रियासत के राजकुमार थे। टिकेन्द्रजीत सिंह महाराजा चंद्रप्रकाश सिंह और चोंगथम चानु कूमेश्वरी देवी की चतुर्थ संतान थे। उन्हें वीर टिकेन्द्रजीत और कोइरेंग भी कहते हैं। वे मणिपुरी सेना के कमाण्डर थे। वे महान देशभक्त और ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजना के घोर विरोधी तथा देश की एकता–अखंडता के कट्टर समर्थक थे। उनका जीवन वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति था और उनका विश्वास था कि "वीरभोग्या वसुन्धरा" अर्थात् वीर ही इस भूमि को भोगने के सच्चे अधिकारी हैं।

सन् 1891 के एंग्लो–मणिपुर युद्ध में मणिपुर के बहादुर लोगों ने औपनिवेशिक शक्तियों का प्रतिरोध जिस वीरता और साहस के साथ किया; वह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है जिसके लिए मणिपुर राज्य प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त के दिन "देशभक्त दिवस" मनाता है।

उन्होने 'महल–क्रान्ति' की जिसके फ़लस्वरूप वर्ष 1891 में अंग्रेज़–मणिपुरी युद्ध शुरू हुआ। इसी कारण उन्हें 'मणिपुर का शेर' कहा जाता है। यहां तक कि ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सरकार ने उनकी वीरता, निडरता तथा पराक्रम की तुलना एक 'खतरनाक बाघ' से की थी। इस परम पराक्रमी और बुद्धिमान सपूत को आमने–सामने के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा नहीं हराया जा सका तो छल–बल का सहारा लेकर एक औपनिवेशिक कानून की आड़ में विशेष अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। और सन् 1891 में 13 अगस्त के दिन बीर टिकेंद्रजीत को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया गया।

यू तिरोत सिंह

1802 में जन्मे यू तिरोत सिंह मेघालय के खासी पहाड़ियों के एक क्षेत्र नोंगखलाव के मूल निवासी थे, जिन्होंने 1829–1833 के एंग्लो–खासी युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में खासियों का नेतृत्व किया था। 4 अप्रैल 1929 को, उनकी सेना ने नोंगखला में तैनात ब्रिटिश गैरीसन पर हमला किया, जिसमें दो अधिकारी मारे गए। तिरोत और उसके लोगों ने छापामार युद्ध में चार साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। 1833 में, जब वह गोली लगने के बाद पहाड़ियों में छिप गए, तो उसके एक आदमी ने उसे धोखा दिया और जल्द ही ब्रिटिश सेना ने उसे पकड़ लिया। उन्हें ढाका भेज दिया गया, जहां 17 जुलाई 1835 को कैद में उनकी मृत्यु हो गई। तिरोत सिंह भारत मां के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने ब्रिटिशों के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया।

कनकलता बरुआ

22 दिसंबर 1924 को असम में जन्मी कनकलता बरुआ को लोग बीरबाला और असम की रानी लक्ष्मीबाई

भी कहते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने महज 18 साल की उम्र में जीवन त्याग दिया। कनकलता बरुआ ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपना नाम बनाया, जब वह केवल 17 वर्ष की उम्र में एक आत्म बलिदानी दस्ते में शामिल हुईं। हालांकि, इससे पहले उन्होंने आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण खारिज कर दिया गया था। भारत छोडो आंदोलन के दौर में असम में 20 सितंबर, 1942 के दिन तेजपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया गया था। कनकलता बरुआ ने इस जुलूस का नेतृत्व किया। वह अपने हाथों में तिरंगा थामे हुए आगे बढ़ रही थीं। थाना प्रभारी ने आगे बढ़ने पर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी कनकलता के कदम पीछे नहीं हटे। कनकलता जैसे ही तिरंगा लेकर आगे बढ़ीं, वैसे ही जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी गई। पहली गोली कनकलता की छाती पर लगी जिसे बोगी कछारी नाम के सिपाही ने चलाई थी। जिसके बाद, तिरंगे को उनके सहयोगी मुकुंद काकोटी ने उठा लिया, उन्हें भी गोली मार दी गई।

पाउना ब्रजबासी

1833 में जन्मे पाउना ब्रजबासी एक मणिपुरी सेनानायक थे। मणिपुर साम्राज्य की सेना में प्रवेश करने के बाद अपनी काबिलियत के दम पर वह 1891 तक मेजर के पद पर पहुंच गए।

उसी वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एंग्लो–मणिपुर युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। पाओना ने 23 अप्रैल 1891 को भारतीय इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाई में से एक में अपने सैनिकों का बहादुरी से नेतृत्व किया। वह जानते थे कि इस युद्ध में उनके लिए लंबे समय तक टिक पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वह घबराए नहीं। यहां तक कि उन्होंने मृत्यु से पहले शत्रु पक्ष ने एक प्रस्ताव दिया था कि यदि वह उनकी तरफ से लड़ने को तैयार हों तो उन्हे जीवनदान दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने देशद्रोह से ज्यादा मौत को स्वीकार करना पसंद किया। पाओना ने अपनी टोपी के चारों ओर लिपटे कपड़े को उतार दिया और ब्रिटिश अधिकारी से उसका सिर काटने को कहा।

रानी गाइदिन्ल्यू

रानी गाइदिनल्यू का जन्म– 26 जनवरी, 1915, मणिपुर, भारत; मृत्यु– 17 फ़रवरी, 1993) भारत की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थीं। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए नागालैण्ड में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए इन्हें 'नागालैण्ड की रानी लक्ष्मीबाई' कहा जाता है। 13 वर्ष की उम्र में ही वह नागा नेता जादोनाग के सम्पर्क में आईं। जादोनाग मणिपुर से अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। वे अपने आन्दोलन को क्रियात्मक रूप दे पाते, उससे पहले ही गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों ने जादोनाग को 29 अगस्त, 1931 को फ़ाँसी पर लटका दिया। जादोनाग के बाद अब स्वतंत्रता के लिए चल रहे आन्दोलन का नेतृत्व बालिका गाइदिनल्यू के हाथों में आ गया। उन्होंने महात्मा गाँधी के आन्दोलन के बारे में सुनकर ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देने की घोषणा की। नागाओं के कबीलों में एकता स्थापित करके उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए क़दम उठाये। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता को देखकर जन–जातीय लोग उन्हें सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे थे। सोलह वर्ष की इस बालिका के साथ केवल चार हज़ार सशस्त्र नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत गाइदिनल्यू ने अंग्रेज़ों की फ़ौज का सामना किया। वह गुरिल्ला युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यन्त निपुण थीं। रानी गाइदिनल्यू को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया। 1947 ई. में देश के स्वतंत्र होने पर ही रानी गाइदिनल्यू जेल से बाहर आ सकीं। स्वतंत्रता संग्राम में साहसपूर्ण योगदान के लिए 'पद्मभूषण' की मानद उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया गया था।

हाइपौ जादोनांग

हाइपौ जादोनांग मणिपुर के समाज सुधारवादी, आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने 20 वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के चंगुल से नागा लोगों को मुक्त करने की मांग की थी। उन्होंने हेराका नामक आंदोलन भी चलाया। इसके अलावा उन्होंने एक सेना का निर्माण शुरू किया, जिसे उन्होंने 'रिफेन' कहा, जिसमें 500 पुरुष और महिलाएं शामिल हुईं। जादोनांग ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की स्तुति गाते हुए गीतों की रचना की, जो उनकी

शिष्या रानी गैडिन्ल्यू ने अपने अनुयायियों को प्रदान की। 19 फरवरी 1931 को, उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बाद में झूठे हत्या के आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी।

मुंगरी उर्फ मालती मेम, लालमती, दरांगी

वह चाय बागानों में अफीम विरोधी अभियान की प्रमुख सदस्यों में से एक थीं। 1921 में, शराबबंदी अभियान में कांग्रेस के स्वयंसेवकों का समर्थन करने के लिए दारांग जिले के लालमती में उनकी हत्या कर दी गई थी।

तिलेश्वरी बरुआ, ढेकियाजुली

वह ढेकियाजुली से भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदार थीं। 20 सितंबर, 1920 को ढेकियाजुली में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश के दौरान पुलिस फायरिंग में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी दिन कनकलता बरुआ की भी मृत्यु हो गई।

कुमाली देवी, ढेकियाजुली

वह एक और बहादुर थीं, जिन्हें 20 सितंबर, 1942 को तिलेश्वरी बरुआ और खाहुली देवी के साथ ढेकियाजुली पुलिस फायरिंग में गोली मार दी गई थी।

यह कार्य अभी अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हजारों शहीदों के विषय में तो कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता। यह छोटा सा प्रयास एक श्रद्धांजलि है उत्तर पूर्व के गुमनाम शहीदों के लिए। ❑❑

विनोद जौहरी: *सेवानिवृत्त अपर आयकर आयुक्त*

पर्यटन से लगेंगे रोजगार को पंख

सेहतमंद पर्यटन मुहैया कराने की दृष्टि से दुनिया में भारत को अव्वल स्थान प्राप्त है। भारत जैसे विरासत के धनी राष्ट्र के लिए यहां के पुरातात्विक धरोहर केवल दार्शनिक स्थल भर नहीं है, बल्कि राजस्व प्राप्ति का स्रोत तथा अनेक लोगों को रोजगार मुहैया कराने का माध्यम भी है।

27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य के पर्यटन मंत्रियों के साथ एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पर्यटन को बढ़ाने के लिए व्यापक विचार–विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में 19 राज्यों के पर्यटन मंत्रियों, पर्यटन सचिवों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। देश के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, भौगोलिक विविधता वाले प्रदेशों ने पर्यटन के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए रणनीति तैयार की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत आज विभिन्न श्रेणी के पर्यटन के लिए दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन गया है। चिकित्सा, पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए यात्री सहज भाव से भारत को वरीयता दे रहे हैं। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टता और संस्कृति है। यह क्षेत्र अपनी भौगोलिक बनावट, जिसमें ठंडा, गर्म, रेगिस्तान, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां विशाल वन क्षेत्र, अंडमान निकोबार जैसे दीप समूह, विभिन्न पर्वत और पठार पर्यटकों को बरबस ललचाते हैं। धार्मिक रूप से समृद्ध होने के कारण भी बड़ी संख्या में दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के लोग यहां आते रहे हैं।

वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट में भारत को पर्यटन के मामले में तीसरा स्थान हासिल है। इस रिपोर्ट में 185 देशों के पिछले 7 वर्षों का प्रदर्शन सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन खर्च, घरेलू पर्यटन खर्च एवं पूंजी निवेश के मांगों को आधार बनाकर निष्कर्ष निकाला गया है। महामारी से पहले भारत प्रतिवर्ष लगभग 25 अरब डालर का राजस्व अर्जित करता रहा, जिसे 2025 तक 120 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह फ्रांस और स्पेन जैसे देशों की तुलना में बहुत अधिक है।

सरकार को विश्व भर में भारतीय संस्कृति विचारधारा चिकित्सा पद्धति के साथ–साथ अचंभित करने वाली भौगोलिक बनावट देश की सुंदरता को प्रमुखता से फैलाने का प्रयास करना चाहिए।

–शिवनंदन लाल

केंद्र की सरकार समावेशी विकास के लिए पर्यटन को उर्वर क्षेत्र मानकर अपनी नीतियां विकसित की हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसे आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। हाल ही में डेनमार्क के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने वहां के सभी भारतीय लोगों से पांच गैर भारतीय लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। 'चलो इंडिया' का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि सभी भारतीय राष्ट्रदूत अगर इस काम में लग जाए तो बाहर के लोगों को भारत को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही मुकम्मल तैयारियां की गई है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के लिए बजट आवंटन भी लगातार बढ़ता रहा है। बीच में कोरोना महामारी के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव आए, पर्यटन की रफ्तार थम सी गई थी। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार भी हुए, पर अनलॉक के बाद पर्यटन ने फिर से गति पकड़ ली है। वित्त वर्ष 2020 में भारत में 39 मिलियन नौकरियां पर्यटन पर आधारित थी, जो देश में कुल रोजगार का लगभग 8 प्रतिशत था। 2029 तक इसके 53 मिलियन तक होने की उम्मीद है। वर्ष 2021 में भारत में कुल

856337 पर्यटक भारत भ्रमण के लिए आए थे।

कोविड के बाद केंद्र सरकार ने विभिन्न पहलुओं के माध्यम से घरेलू पर्यटन को भी गति देने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार ने 'देखों अपना देश' की शुरुआत की है, जिसके तहत विभिन्न प्रचार, गतिविधियों जैसे वेबीनार, ऑनलाइन प्रतिज्ञा, प्रश्नोत्तरी से कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि घरेलू पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके। भारत एक साल के लिए जी–20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। अध्यक्षता का यह समय आगामी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चलेगा। इस दौरान देश के लगभग 55 शहरों में जी–20 से जुड़ी लगभग 215 बैठकें और अन्य आयोजन प्रस्तावित हैं। सरकार भारत को मिली इस अध्यक्षता को विदेशी पर्यटन के लिहाज से बेहतर मौके की तरह देख रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का मानना है कि भारतीय पर्यटन को विश्व मंच पर पेश करने का यह सुनहरा मौका है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वे अपने यहां के पर्यटन उत्पादों और डेस्टिनेशंस को इस तरह तैयार करें कि यहां आने वाले मेहमान उनसे प्रभावित और आकर्षित हो। अध्यक्षता के बहाने मिले मौके पर सरकार अपने देश की ऐसी पारंपरिक चीजों के पहलुओं को दिखाना चाहती है जो अपने आपमें अनूठी हो। मालूम हो कि जी–20 से जुड़े आयोजनों में चार आयोजन पूरी तरह से पर्यटन आधारित होंगे। यह चारों कार्यक्रम गुजरात के कच्छ, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, जम्मू कश्मीर और गोवा में किए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि इन सभी पर्यटक स्थलों पर प्रमुखता से भारत की आन, बान, शान तिरंगा को भी लहराया जाएगा।

वैश्विक स्तर पर पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। यह कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करता है तथा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आंकड़े की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग **5 लोगों** को रोजगार मिला हुआ है। सरकार की तरफ से जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान भारत को ट्रैवल एंड टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख नई नौकरियां मिलने का अनुमान है। पर्यटन उद्योग में निरंतर आ रहे उछाल से इस क्षेत्र में प्रगति है। पर्यटन से भारत में महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसरों की खिड़की खुली है। वैश्विक स्तर पर भारत में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्यटन क्षेत्र में दोगुना से अधिक महिलाएं कार्यरत है। इस दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ समानता और सामाजिक न्याय का भी माध्यम बना है। आज भारत का प्रयोग अपने पारंपरिक डायरो से निकलकर चिकित्सा और योगा जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है, इसलिए यहां अवसर भी बढ़ रहे हैं।

सरकार ने इसे और अधिक गति देने की गरज से पर्यटन सर्किट के विकास से स्वदेश दर्शन योजना, विरासत स्थलों के विकास हेतु हृदय योजना तथा धार्मिक स्थलों के लिए प्रसाद योजना शुरू की है। पर्यटन स्थलों पर रोपवे के निर्माण तथा रेलवे स्टेशनों लॉजिस्टिक पार्क के आसपास विकास की गति तेज कर दी है। विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने के लिए 166 देशों के लिए वीजा की शुरुआत हुई है। आगे इसके शुल्क में कमी लाने का भी प्रस्ताव है। अपनी विरासत के प्रति लगाव विस्तृत करने के लिए 'धरोहर गोद लो योजना' तथा विदेशों में भारतीय धरोहरों को लोकप्रिय बनाने के लिए 'देखो अपना देश' नाम से पर्यटन पर्व का अनुष्ठान तथा राज्यों के विशेष स्थलों में पर्यटन समारोह पर्यटन सभी के लिए का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने अतुल्य भारत का नया पोर्टल लांच कर सभी आवश्यक जानकारियों को सुलभ कराया है। मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, उत्तर प्रदेश के सारनाथ और बिहार के बोध गया जैसे स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। रात्रि कालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने देश के 10 ऐतिहासिक स्मारकों को आगंतुकों के लिए रात में 9:00 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया है। वहीं गृह मंत्रालय में 137 चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय किया है।

भारत सरकार द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद पर्यटन प्रणाली के समक्ष कई चुनौतियां अभी नहीं बनी हुई है। वैश्विक मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचा का अभाव पर्यटन के राह में बड़ा रोड़ा है। कम बजट आवंटन के कारण आर्थिक व सामाजिक और संरचना की रफ्तार भी धीरे है। सफल स्वच्छ भारत अभियान के बाद भी देश में यत्र–तत्र फैली गंदगी से पार पाना अभी भी बाकी है। सुरक्षा सर्वेक्षण में भी भारत का स्थान दुनिया के मानकों पर बहुत नीचे है। स्वास्थ, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, साहसिक पर्यटन में अपार संभावना है, पर इसमें सरकार अभी अपेक्षित निवेश नहीं कर पा रही है।

ऐसे में 'अतुल्य भारत' और 'अतिथि देवो भव' की उदास भावना के साथ अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उड़ान योजना का विस्तार हो तथा सभी राज्यों को पुरातत्व सर्वेक्षण की सहायता से अपने धरोहर स्थलों के लिए यूनेस्को के मानकों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। सरकार को विश्व भर में भारतीय संस्कृति विचारधारा चिकित्सा पद्धति के साथ–साथ अचंभित करने वाली भौगोलिक बनावट देश की सुंदरता को प्रमुखता से फैलाने का प्रयास करना चाहिए। ❑❑

स्वावलंबन का शंखनाद

स्वावलंबी भारत अभियान की संकल्पना पर सरकार्यवाह **माननीय दत्तात्रेय होसबाले** द्वारा दिये गये संबोधन के मुख्य अंश

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वावलंबी भारत अभियान की दो दिवसीय अखिल भारतीय योजना बैठक, दिल्ली स्थिति हरियाणा भवन में संपन्न हुई। बैठक को ऑनलाईन संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि महात्मा गाँधी जी और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रेरणा लेकर देश के लिए काम करने के अपने संकल्प को पुनः चेतनायुक्त बनाएँ ओर भारत को एक श्रेष्ठ, समृद्धिशाली, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करने की प्रेरणा से हम सब आगे बढें।

दिनांक 30 सितंबर 2022 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2022 तक चली योजना बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधिक करते हुए श्री दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि पूर्व की सरकारों की गलत नीति के कारण गांव से शहरों की ओर पलायन होने लगा है। शहरों की स्थिति भी खराब होती जा रही है। वर्तमान सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है तथा सरकार ने स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। सरकार को चाहिए कि लघु उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि खाद्यान्न, आयुर्वेद की दवा आदि क्षेत्रों में गांवों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार का प्रयोग करें, नये–नये उपक्रम करें। स्थानीय कौशल को पुनर्जीवित करते हुए स्थानीय स्तर पर योजना बनें। मेक इन इंडिया को सही मायनों में धरातल पर उतारा जाए, किसानों को उपज के उचित दाम मिलें, उपज के लिए प्रसंस्करण ईकाईयां लगाई जाए। किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने के लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि बीते 75 वर्षों में कई प्रकार की चुनौतियों व संकट का सामना करने के पश्चात भी देश ने कई आयामों में प्रगति की है। सुरक्षा क्षेत्रों में हो, विज्ञान और तंत्र ज्ञान के विभिन्न आयामों में हो, चिकित्सा, दवा के क्षेत्र में हो, भारत ने विशेष तरक्की की है। भारत ने जिस प्रकार अपने पैरों पर खड़े होने का एक सार्थक प्रयास किया है। इसकी आज विश्व में सराहना भी हो रही हैं। आज भारत का विश्व के अर्थ संपन्नता की दृष्टि से स्थान सबसे ऊपर के छह देशों में एक है। शीघ्र ही हम और तरक्की करने के लिए अग्रसर हें। उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, यह विश्वास हम सब रखते हैं।

आर्थिक असमानता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पर केपिटा इनकम की दृष्टि से 2020 में 1 लाख 35 हजार रुपये की तुलना में 2022 में 1 लाख 50 हजार पर केपिटा इनकम के आंकड़े हमारे सामने हैं। बेरोजगारी की संख्या पिछले जून में लगभग 4 करोड़ थी, 2.2 करोड़ रूरल एरिया में तथा 1.8 करोड़ अर्बन एरिया में। लेबर फोर्स सर्वे के अभी–अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7.6 प्रतिशत बेरोजगार है। देश में गरीबी, बेरोजगारी इसके साथ–साथ और एक विषय के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा, वो है – आर्थिक असमानता (इनइक्वैलिटी)। भारत में टॉप 1 प्रतिशत आबादी की इनकम देश के इकोनॉमी की 20 प्रतिशत है तथा 50 प्रतिशत लोगों की इनकम देश की 13 प्रतिशत ही है। तो इस असमानता के संदर्भ में भी हमें सोचना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच और आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज के बहुत सारे संगठन, संस्थाएँ, स्वावलंबी भारत निर्माण कराने के अभियान की तरफ आगे बढ़ी हैं। सरकार ने एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात की, जिस की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता भारत का मंत्र बनना ही चाहिए। भारत को स्वदेशी के आधार पर स्वावलंबी बनाना केवल कोई सपना नहीं है, यह भारत के अंदर की ताकत है, क्षमता है।

सरकार्यवाह ने कहा कि सरकार भी कई प्रकार की योजनाएं सामने लेकर आई, जैसे– पशुधन के संदर्भ में, मत्स्य पालन के संदर्भ में, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए एफपीओ जैसी योजनाएं आदि। इन सारे कारणों से देश के अंदर एक वातावरण बनने में सहायता मिली। यही कारण है पिछले 4–6 महीनों में स्वावलंबी भारत अभियान की योजनाएं

स्वावलंबी भारत अभियान में चार मार्ग बताए गए हैं – 1. विकेंद्रीकरण, 2. स्थानीय स्वदेशी, 3. उद्यमिता (इंटरप्रिनयोरशिप (स्किल डवलपमेंट सहित)) और 4. सहकारिता। इन चार आधार स्तंभों के आधार पर देश में हम इस अभियान को सफल बनाएं।

जिले के नीचे खंड स्तर तक, ग्राम स्तर तक कैसे फेलती जा रही हैं, यह प्राप्त सूचनाओं से स्पस्ट है। यह एक सार्वदैशिक, सार्वभौमिक व्यापक अभियान बनता जा रहा है। इसलिए प्रत्येक ब्लाक में कार्य करना पड़ेगा, प्रत्येक गांव तक इस योजना को फैलाने के लिए, जहाँ अभी भी पहुंचे नहीं है, वहाँ पहुंचाने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। सरकार के प्रयास के साथ–साथ समाज के प्रयास होने चाहिए। इस अभियान में जो लोग जुड़ सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं ऐसे संस्थान, ऐसे व्यक्ति, इन सभी लोगों को जोड़कर समन्वित प्रयास होने चाहिए।

श्री होसबाले जी ने कहा कि योजनाएं केवल अखिल भारतीय स्तर पर बनाने से काम नहीं बनेगा, इसलिए स्थानीय योजना यानि विकेंद्रीकरण इसकी आवश्यकता है। इस विकेंद्रित योजना से, परस्पर सहकार और समन्वय से, इन बातों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो सकता है, कृषि के संदर्भ में, बीज के, फल के, सब्जी के, फूलों के हैं, कोल्ड स्टोरेज के संदर्भ में, मार्केटिंग के संदर्भों में हैं, इन सारे संदर्भों में हमें विचार करना पड़ेगा। कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग की कई प्रकार के चीजें, कुछ समय में जो नष्ट हो गई हैं, उसको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, ऐसे ही दवा के क्षेत्र में स्थानीय कई प्रकार के आयुर्वेद की चीजें बन सकती है।

उन्होंने बताया कि नए स्टार्टअप को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने के कारण बड़ी संख्या में स्टार्टअप आज दिखाई दे रहे हैं। उद्यमिता में जिनकी रुचि है ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इसके साथ साथ प्रशिक्षकों की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होगी क्योंकि हमें जिले के नीचे के स्थानों पर, छोटे नगर में, खंड केंद्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक महा अभियान चलाना है।

उन्होंने कहा कि उद्यमिता की दृष्टि से देखें तो कौशल केंद्र की स्थापना और इंटरप्रीनयोरशिप के लिए एक वातावरण बनाना पड़ता है। कॉलेज से निकलने वाले लोगं सरकारी नौकरी की तरफ या प्राइवेट नौकरी की तरफ जो सेलेरी देने वाली नौकरी है, उसकी तरफ देखने से देश के अंदर उतनी नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसलिए नौकरी पाने वाले के स्थान पर नौकरी देने वाले बनें, इस बात के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? इंटरप्रीनयोरशिप, उद्यमिता के माध्यम से।

उन्होंने कहा कि युवकों को लगता है कि केवल व्हाइट कॉलर जॉब में, आज समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन मनुष्य जीवन के लिए सब प्रकार के कार्य की एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा, ऐसा नहीं हो सकता।

शहर और गांव के बारे में, छोटे काम और बड़े काम की दृष्टि के बारे में, शरीर श्रम और श्रम से बचने के प्रयत्न के बारे में, इन सारे विषयों में मानसिकता के परिवर्तन की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि भारत सोने की चिड़िया रही है, भारत एक सम्पन्न राष्ट्र रहा अनेक शतकों तक, इसीलिए तो इस देश पर आक्रमण हुए। 2000 वर्षों के विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक विषय क्षेत्रों के अध्ययन करने वाले एंग्स मेडिसिन के अनुसार उस समय भारत का वर्ल्ड ट्रेड में 25 प्रतिशत हिस्सा था। विलियम डेम रिमप्ल ने बताया है कि 1600 ईस्वी तक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पहले तक भारत की जीडीपी वर्ल्ड की वन फॉरथ ऑफ जीडीपी थी। लेकिन 75 वर्षों मे देश स्वतंत्र होने के बाद तो हमें यह सब ठीक करना चाहिए था। विश्व के ऐसे कई राष्ट्र भी है जिन्होंने अपने आपको सुधार लिया, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान की स्थिति क्या थी? इजराइल में तो 1948 में ही अपनी मातृभूमि पर यहूदी लोगों ने आकर उस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किये और वो आज कहाँ पहुंच गए? परिश्रम के, राष्ट्रभक्ति के, समाज को लेकर चलने के, मानसिकता के, देश के प्रति श्रद्धा और आदर रखने के स्वभाव में, हम इन देशों से प्रेरणा ले सकते हैं। इन चीजों को यदि हम देखें तो अपने देश में भी आर्थिक कायाकल्प करना बहुत असंभव नहीं है। अब इस दिशा में देश आगे बढ़ भी रहा है।

स्वावलंबी भारत अभियान में चार मार्ग बताए गए हैं – 1. विकेंद्रीकरण, 2. स्थानीय स्वदेशी, 3. उद्यमिता (इंटरप्रिनयोरशिप (स्किल डवलपमेंट सहित)) और 4. सहकारिता। इन चार आधार स्तंभों के आधार पर देश में हम इस अभियान को सफल बनाएं।

इस देश व्यापी स्वावलंबी भारत अभियान की सराहना करते हुए उन्होंने कामना की कि आने वाले दिनों में इस अभियान को हर प्रकार की सफलता मिले। यह अभियान एक सार्थक अभियान के रूप में प्रतिस्थापित होकर देश के अंदर एक सफल आर्थिक क्रांति लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य देगा। भारत को समृद्ध व सशक्त बनाने की दृष्टि से हम संकल्प लेकर आगे बढ़ें। ❑❑

रिश्वतखोरी ही है फ्रीबीज, इसे रोकने के लिए कानून चाहिएः डॉ. महाजन

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली फ्रीबीज (चुनावों के दौरान मुफ्त उपहारों की पेशकश) को 'रिश्वत का ही एक स्वरूप' करार दिया है और कहा है कि इसके लिए एक कानून पेश करके इस परिपाटी को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। कई सारे मुद्दों पर दिप्रिंट से बात करते हुए, महाजन ने कहा, 'मुफ्त उपहार वास्तव में मतदाताओं के लिए एक प्रकार की रिश्वत है, और इस रिश्वतखोरी को रोकना होगा। चाहे यह किसी एक पार्टी द्वारा हो या दूसरी पार्टी की तरफ से, इसे कानून द्वारा रोकना होगा।'

इस बीच भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव भेज उनसे जवाब मांगा है, जिसमें उन्हें चुनावी घोषणापत्रों में किए गए वादों के 'वित्तीय निहितार्थ' और उनके लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के 'तरीकों और साधनों' का विवरण प्रस्तुत करने की बात कही है। यह कदम इस साल की शुरुआत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 'रेवडी संस्कृति' (फ्रीबी कल्चर) वाली टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट की तीन–न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष 'राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले मुफ्त उपहारों के बेतुके वादों' को चुनौती देने वाली एक याचिका के बाद 'मुफ्तखोरी' पर छिड़ी एक तीखी बहस के ठीक बाद उठाया गया है।

उन्होंने तर्क दिया, 'मुफ्त उपहार वास्तव में वे चीजे/सेवाएं होती हैं, जिनकी कीमत तय की जा सकती है और जो सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। अर्थशास्त्र में, हम हमेशा कहते हैं कि संसाधन सीमित हैं और सार्वजनिक राजस्व भी सीमित है। हमारे पास सीमित संसाधन ही उपलब्ध हैं, इसलिए इन संसाधनों का उपयोग या तो राज्य के विकास के लिए या फिर मुफ्त उपहारों को देने के लिए किया जा सकता है। किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए?'

महाजन ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान, 15 वर्षों के लिए विकास व्यय की वृद्धि दर सालाना लगभग 20 प्रतिशत थी, जो कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले पांच साल में घटकर 9 प्रतिशत रह गई है।

महाजन ने कहा, 'यह संज्ञात्मक आधार (नॉमिनल बेसिस) पर है। वास्तविक आधार पर यह उससे काफी कम है। इसलिए, यह विकास में, या यूं कहें कि दिल्ली में विकास के प्रयासों की कमी में, परिलक्षित हो रहा है – कोई नया स्कूल नहीं बना है, कोई नया कॉलेज नहीं खुला है, कोई नया अस्पताल नहीं खुला है, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना है, दिल्ली में कुछ भी नहीं बदला है। इसलिए, अगर कोई कहता है कि मैं समाज के गरीब तबके के लिए ये मुफ्त सुविधाएं प्रदान कर रहा हूं, तो वह सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि समाज के गरीब वर्ग को अच्छे परिवहन, अच्छी सड़कों, अच्छी सुविधाओं की आवश्यकता है, ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें।'

उन्होंने कहा, 'अगर हम हर किसी को मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो लोग इसके लिए भुगतान कर सकते थे वे भी वास्तव में इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसलिए, वे संसाधन राज्य अथवा शहर के विकास के लिए उपलब्ध नहीं कराए जा पाएंगे. और यह एक तरह की छूत की बीमारी है, यह बीमारी दूसरे राज्यों में भी फैलती जा रही है।'

महाजन ने कहा कि राजनीतिक दल भी इस दौड़ में शामिल हैं क्योंकि 'सत्तारूढ़ होना विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जिसका अर्थ यह है कि राजनीतिक आकांक्षाएं आम लोगों के कल्याण पर हावी हो जायेंगीं।'

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को उजागर करने वाली आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाजन ने कहा कि इसी बात को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी स्वीकार किया था।

महाजन ने कहा, 'बेरोजगारी की समस्या कई दशकों से चली आ रही है, और विशेष रूप से 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाने के बाद से यह समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इसे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी स्वीकार किया था, जब उन्होंने कहा था कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि वास्तव में एक रोजगारहीन विकास है। वह इसे बार–बार कहते रहे थे और इसलिए, ऐसा कहना कि यह बेरोजगारी के अस्तित्व में होने की

स्वीकृति है, वास्तव में सही नहीं है।' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वाले खड़े करने की ज्यादा जरूरत है।

वैश्विक उथल–पुथल और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में बात करते हुए, महाजन ने कहा कि भारत ने हमेशा से 'आपदा में अवसर' खोजा है और इसके लिए उन्हों कोविड –19 महामारी का उदाहरण दिया है।

उन्होंने कहा, 'अब, जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो हम पाते हैं कि कई देश खाने के सामान की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के माध्यम से रूस को खत्म करने में सक्षम होंगे, लेकिन वास्तव में ये प्रतिबंध खुद इन पश्चिमी देशों को ही कष्ट दे रहे हैं, जो अब अन्य चीजों के अलावा गैस और तेल की उपलब्धता के मामले में भारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारी मुद्रा और अन्य सभी मुद्राएं अवमूल्यन (मुद्रा कीमतों का काम होना) का सामना कर रही हैं, लेकिन हमारी मुद्रा का प्रदर्शन अभी भी अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में बेहतर है।'

उन्होंने कहा, इसे देश द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने और 'आत्मनिर्भर पथ' पर आगे बढ़ने के एक अवसर के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने दावा किया, 'पश्चिमी देशों से आ रही खबरों के मुताबिक वे सभी मंदी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका भी मंदी का सामना कर रहा है और भारत को अपना उत्पादन बढ़ाने की संभावना मिल गयी है। अगर हम पिछली कुछ तिमाहियों की तरफ देखें, तो हमारी जीडीपी काफी तेज दर से बढ़ रही है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए हैं।'

महाजन ने कहा, 'दूसरी ओर, विकसित देश मंदी का सामना कर रहे हैं। उनकी जीडीपी सिकुड़ रही है, जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिकी जीडीपी पिछली दो–तीन तिमाहियों से लगातार सिकुड़ रही है। इसलिए, यह हमारे लिए एक अवसर है। यूक्रेन युद्ध के कारण हमें किसी खास समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है – भोजन की नहीं, गैस और तेल की भी नहीं। बल्कि इसकी वजह से हमें रूस से सस्ता तेल और गैस मिल रहा है।'

महाजन ने कहा कि पाउंड, यूरो या येन सहित बाकी मुद्राओं से तुलना करने पर पता चलता है कि उनमें भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग दो या तीन गुना अवमूल्यन हुआ है।

https://hindi.theprint.in/politics/rss-affiliate-sjm-ashwini-mahajan-said-bribery-is-freebies-law-is-needed-to-stop-it/407949/

हर देशवासी का राष्ट्रीय मंत्र होना चाहिए आत्मनिर्भरता: दत्तात्रेय होसबाले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार

का अभियान 'आत्मनिर्भर भारत' सभी देशवासियों का राष्ट्रीय मंत्र होना चाहिए। यह हर देशवासी के दिल में होना चाहिए, तभी हम देश को फिर से उस स्थिति में लेकर जा पाएंगे, जहां वह गुलामी से पूर्व था।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित स्वावलंबी भारत अभियान के तहत 'स्वावलंबन का शंखनाद' विषय पर आयोजित गोष्ठी को आनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने गरीबी और बेरोजगारी कम करने के मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि कुछ वर्षों में स्थिति में बदलाव आया है। देश अब गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े घटने के साथ देश ने विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाया है। हालांकि, होसबाले ने लगे हाथ अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के मात्र एक प्रतिशत लोगों के पास खूब पैसा है, जबकि करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिनकी प्रतिदिन की आय 400 रुपये से भी कम है। इसके लिए उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की आर्थिक नीतियों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि इन सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

सुधार के लिए माहौल तैयार नहीं किया और नीतियां नहीं बनाई, जिसके चलते यह समस्या मुंह बाए खड़ी है। शहरों को ही सुविधा केंद्रित रखा गया। शिक्षा भी उस तरह नहीं थी। इस कारण गांवों से युवा शक्ति का पलायन हुआ तो शहरों का अनियोजित विकास हुआ। अब शिक्षा नीति में बदलाव आया है तो स्थिति निश्चित ही सुधरती दिखेगी।

उन्होंने संघ द्वारा चलाए जा रहे स्वावलंब भारत अभियान को गांव व छोटे शहरों तक ले जाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे हर किसी को जोड़ना होगा। साथ ही इसे लेकर स्थानीय स्तर पर और अध्ययन की जरूरत है।

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-rss-general-secretary-dattatreya-hosabale-says-self-reliance-should-be-national-mantra-of-every-countryman-23113957.html?s=08

भारत में निर्मित वस्तुओं से ही आत्मनिर्भर होगा देश: स्वजाम

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर संवाद का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय संयोजक सुंदरम ने संगठन के बारे में विस्तार से

जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित वस्तुओं से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की जरूरत है।

भारत के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के 15 संगठन मिलकर रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक स्वालंबन की दिशा में काम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के स्वदेशी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक आर सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल, सह संगठक सतीश कुमार, मध्य क्षेत्र के संगठक केशव जी ने रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक सतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ फैक्ट्री या दुकान शुरू करना निर्माण कार्य नहीं है। अपने हुनर का इस्तेमाल करके भी स्वरोजगार किया जा सकता है। उन्होंने एक छात्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने नृत्य को स्वरोजगार का माध्यम बनाया। कोरोना काल में वर्चुअल प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा को अवसर में बदलते हुए 100 करोड़ का टर्नओवर किया। वह छात्रा 250 से अधिक युवक–युवतियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रही है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता में 25 सितंबर से दो अक्टूबर के मध्य कम से कम 100–100 युवकों एवं युवतियों का पंजीयन कराए। इसके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। मध्य क्षेत्र के संगठक केशव जी ने लोगों को स्वदेशी का महत्व बताते हुए निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन सुमन मुथा, आभार प्रदर्शन स्वदेशी जागरण मंच के नगर प्रमुख प्रवीण साहू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक मोहन पवार, स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक जगदीश पटेल उपस्थित थे।

https://www.naidunia.com/chhattisgarh/raipur-swadeshi-jagran-manch-inspired-youth-to-make-self-employment-7810925

भूगोल की जानकारी और इतिहास पर गर्व जरुरीः मोहन भागवत

सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि विकास के लिए भारत को किसी दूसरे देश का अनुसरण करने की बजाए भारत बनकर ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन, रूस, अमेरिका बनने का प्रयास करेंगे, तो वह नकल करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर लोग तमाशा देखने जरूर आयेंगे लेकिन वह भारत का विकास नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास तथा उसके धन एवं रण गौरव को निरंतर गलत बताने वाले लोगों पर विश्वास करना गलती थी और विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने के लिये भूगोल की जानकारी एवं इतिहास पर गर्व करना जरूरी है। भागवत ने 'कनेक्टिंग विद द महाभारत' पुस्तक का विमोचन करते हुए यह बात कही । सरसंघचालक ने कहा, ''कुछ लोगों ने प्रयत्न किये कि हम अपने देश को, अपने इतिहास को भूल जाएं। वे हमें बता रहे थे कि हमारे इतिहास में कुछ नहीं है, कोई धन गौरव, रण गौरव नहीं है।

वे हमारे ग्रंथों को गलत बता रहे थे। '' भागवत ने कहा कि ऐसे लोग इस तरह की बातें इसलिये कह रहे थे क्योंकि उन्हें स्वार्थ साधना था। उन्होंने कहा कि महाभारत, रामायण को कविता, कहानी बताया गया। लेकिन यह समझना जरूरी है कि क्या कोई कल्पना इतनी लम्बी चलती है? भागवत ने कहा कि वेद व्यास को सिंहासन की आस नहीं थी और वे एक ऋषि थे, ऐसे में महाभारत में व्यास गलत क्यों बोलेंगे? उन्होंने कहा कि सुख और दुख आने जाने वाली बात है और हमें अपने धर्म पर कायम रहना चाहिए.. यही महाभारत का बोध है।

सरसंघचालक ने कहा कि भारत को किसी दूसरे देश का अनुसरण करने की बजाए भारत बनकर ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन, रूस, अमेरिका बनने का प्रयास करेंगे, तो वह नकल करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर लोग तमाशा देखने जरूर आयेंगे लेकिन वह भारत का विकास नहीं होगा।

भागवत ने कहा कि हमारी गाड़ी अब विकास की ओर मुड़ गई है और हम उस ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस उद्देश्य के लिये एक लम्बा लक्ष्य लेकर चलना होगा और उस पर आगे बढ़ते रहना होगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इसके लिये इतिहास और भूगोल की जानकारी चाहिए तथा अपने इतिहास पर गौरव होना चाहिए।

https://amritvichar.com/india-has-to-remain-as-india-for-sustainable-development-mohan-bhagwat/

स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना

केंद्र सरकार की ओर से स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब देश में स्टार्टअप्स बैंकों से एक निश्चित सीमा में बिना कुछ गिरवी रखे लोन ले पाएंगे। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, 6 अक्टूबर और उनके बाद मंजूर हुए लोन को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। विभाग के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मेंबर इंस्टीट्यूशन इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को लोन दे सकते हैं।

इस योजना के जरिए देश की स्टार्टअप कंपनियों को फंड जुटाने में मदद मिलेगी। सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप्स बिना

कुछ गिरवी रखकर केवल योजना की शर्तों को पूरा करके लोन ले सकते हैं। मेंबर इंस्टीट्यूशन में बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और एआईएफ को शामिल किया जाता है।

स्टार्टअप्स को इस योजना के तहत लोन लेने के लिए कुछ शर्तों पर खरा उतरना होगा। आपका स्टार्टअप इस स्तर पर कारोबार कर रहा हो, जहां से उन्हें लगातार नियमित आ रही हो। पिछले 12 महीने के स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना चाहिए। इसके साथ ही स्टार्टअप का पहले का कोई भी लोन एनपीए नहीं होना चाहिए।

डीपीआईआईटी की ओर से बताया गया कि सीजीएसएस योजना में कोई भी स्टार्टअप अधिक 10 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकता है। इस योजना में भारत सरकार की ओर से एक ट्रस्ट या फिर फंड स्थापित किया जाएगा, जो लोन के लिए गारंटी देने का काम करेगा। इस प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड की ओर से किया जाएगा।

https://www.jagran.com/business/biz-govt-notifies-credit-guarantee-scheme-for-startups-23123926.html

दिल्ली–मुंबई समेत 8 शहरों में 5जी सर्विस शुरु

टेलीकॉम की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल ने 6 अक्टूबर से अपनी एयरटेल 5जी प्लस सर्विस 8 शहरों में शुरू कर दी है। एयरटेल ने एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि कस्टमर्स रोलआउट पूरा होने तक अपने मौजूदा डेटा प्लान पर ही 5जी सर्विसेस का आनंद ले सकते हैं। कंपनियों द्वारा देश के 8 शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में एयरटेल 5जी प्लस सर्विस लॉन्च कर दी गई है। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो एयरटेल की 5जी प्लस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोलआउट पूरा करना जारी रखे हुए है। कंपनी का कहना है कि 2023 तक पूरे देश में 5जी सेवा का विस्तार कर दिया जाएगा।

https://money.bhaskar.com/business/news/airtel-customers-in-8-cities-including-delhi-mumbai-can-go-5g-on-existing-data-plans-without-changing-4g-sim-130406486.html

कैसे काम करेगा ई–रुपया

आरबीआई की ओर से डिजिटल रुपये (ई–रुपये) को लेकर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया गया है। डिजिटल रुपये का एलान इस वित्त वर्ष के बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। आरबीआई की ओर से जारी किए गए कांसेप्ट नोट में बताया गया है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण करने के लिए सीमित उपयोग के साथ जल्द ही ई–रुपये का पायलट प्रोजेक्ट को लांच करेगा। डिजिटल रुपये के अंतिम रूप पर फैसला पायलट

प्रोजेक्ट से मिले फीडबैक के आधार पर ही आरबीआई की ओर से लिया जाएगा।

ई–रुपये का डिजिटल अवतार टोकन आधारित होगा। इसका मतलब यह है कि आप जिस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं, उसकी पब्लिक 'की' के जरिये भेज सकते हैं। ये एक ईमेल आईडी जैसा हो सकता है। आपको पैसे भेजने के लिए प्राइवेट की या पासवर्ड डालना होगा। बता दें, ई–रुपया बिना इंटरनेट के भी कार्य करेगा। हालांकि इस पर विस्तार से जानकारी आनी बाकी है।

आरबीआई के कांसेप्ट नोट में बताया गया है कि ई–रुपये पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे का कारण बताते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर ये कदम उठाया जाता है, तो बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालकर बैंकों से ई–रुपये में बदलने में जुट सकते हैं।

https://www.jagran.com/business/biz-how-will-e-rupee-work-how-much-will-be-different-for-bitcoin-23126137.html

विश्व बैंक ने की भारत की तारीफ

कोरोना काल में देश के गरीबों की असाधारण ढंग से मदद करने के लिए विश्व बैंक ने भारत की तारीफ की है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि कोविड–19 महामारी के दौर में भारत ने गरीब और जरूरतमंदों की जिस तरह मदद की वह तारीफ–ए–काबिल है।

विश्व बैंक ने 'गरीबी एवं पारस्परिक समृद्धि रिपोर्ट' जारी करते हुए कहा कि दूसरे देश को भी भारत से सबक लेना चाहिए। उन्हें भारत की तरह कदम उठाना चाहिए और गरीबों को सब्सिडी की बजाए नकद प्रत्यक्ष हस्तांतरण करना चाहिए। विश्व बैंक ने कहा कि महामारी की सबसे बड़ी कीमत गरीब लोगों को चुकानी पड़ी है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख ने कहा कि महामारी के कारण गरीब देशों में गरीबी बढ़ गई। इन देशों में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं सामने आईं जो अधिक अनौपचारिक हैं। ऐसी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां सामने आईं जो कमजोर हैं और ऐसी वित्तीय प्रणालियां दिखीं, जो कम विकसित हैं। इसके बाद भी कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी काल में कामयाबी पाई। ❑❑

https://www.amarujala.com/business/business-diary/world-bank-praises-india-for-helping-poor-during-covid-period

स्वदेशी गतिविधियां

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

(Entrepreneurship Encouragement Conferences)

सचित्र झलक

बिलासपुर, छत्तीसगढ़

इंदौर, म.प्र.

उत्तराखण्ड

रंगीन पृष्ठ

अरावली, गुजरात

रायपुर, छत्तीसगढ़

चित्रकूट, म.प्र.

केरल

चित्तौड़, राजस्थान

नरसारापेट, आंध्र प्रदेश

राजगढ़, म.प्र.

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अक्टूबर 2022
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

KIRA FOODS

PRODUCTS INDIA PVT LTD

mail@kirafoodproducts.com 8750506999 www.kirafoodproducts.com

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती